उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 6 अंक 19 1-15 अक्टूबर 2023 ₹ 20/-

क्या अरब-इजरायल संघर्ष तीसरे विश्व युद्ध का रूप लेगा?

- इस्लामिक आतंकियों के मकड़जाल में भारत
- लाखों अफगानों के पाकिस्तान से निष्कासन से तनाव
- तुर्किये की संसद पर आतंकी हमला
- पांच राज्यों के चुनाव और मुसलमान

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

इस्लामिक आतंकियों के मकड़जाल में भारत 04
मुस्लिम नेताओं के निशाने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 07
बाटला हाउस एनकाउंटर केस के आरोपी को उच्च न्यायालय से राहत 12
पांच राज्यों के चुनाव और मुसलमान 14
उर्दू अखबारों के निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी 18

विश्व

लाखों अफगानों के पाकिस्तान से निष्कासन से तनाव 22
मालदीव चीन की गोद में 24
ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त को गुरुद्वारे में जाने से रोका गया 25
पाकिस्तान में आतंकी घटनाओं में वृद्धि 26
बांग्लादेश में डेंगू महामारी जोरों पर 27

पश्चिम एशिया

क्या अरब-इजरायल संघर्ष तीसरे विश्व युद्ध का रूप लेगा? 28
तुर्किये की संसद पर आतंकी हमला 36
सऊदी अरब में 21 वर्ष से कम उम्र के घरेलू कर्मचारी रखने पर प्रतिबंध 38
नरगिस मोहम्मदी को नोबेल पुरस्कार दिए जाने की ईरान द्वारा आलोचना 38
सीरिया में सैन्य अकादमी पर ड्रोन हमले में 100 से अधिक कैडेटों की मौत 39

सारांश

हमास के आतंकियों द्वारा इजरायल पर हमले के बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इजरायल का समर्थन किया है और उस पर हुए आतंकी हमले की निंदा की है वह देश के मुसलमानों और विपक्ष के अधिकांश नेताओं को पसंद नहीं आई है। उर्दू अखबारों ने संपादकीय लिखकर मोदी सरकार की आलोचना की है और कहा है कि उसने पीड़ित फिलिस्तीनियों के समर्थन की बजाय आक्रांता इजरायल का समर्थन किया है और यह भारत की परंपरागत विदेश नीति के खिलाफ है। उर्दू अखबारों का कहना है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी आजाद फिलिस्तीन का समर्थन किया था और इजरायल से यह आग्रह किया था कि वह उन क्षेत्रों को खाली कर दे जिस पर उसने युद्ध के दौरान कब्जा किया था। खास बात यह है कि तीन बहुचर्चित विश्वविद्यालयों जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों ने भी मोदी सरकार की फिलिस्तीन नीति के विरोध में प्रदर्शन किए। देश भर की मस्जिदों में 'अल-अक्सा मस्जिद बचाओ' दिवस मनाया गया और मुसलमानों ने विभिन्न नगरों में इजरायल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए। हालांकि, भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह स्पष्ट कहा है कि फिलिस्तीन के प्रति भारत के रूख में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और वह अब भी आजाद फिलिस्तीन के पक्ष में है।

पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों की धमक शुरू होते ही उर्दू के अखबारों ने मुसलमानों से अपील की है कि वे इन चुनावों के बारे में अपनी रणनीति स्पष्ट करें और भाजपा के खिलाफ मतदान करके मुस्लिम विरोधी मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल कर दें। अधिकांश उर्दू अखबारों ने भाजपा के अंदरूनी मतभेदों का विस्तृत वर्णन किया है और यह मत व्यक्त किया है कि संघ व भाजपा हाईकमान पार्टी के क्षेत्रीय क्षत्रपों को नजरअंदाज करके विधानसभा के इन चुनावों को सिर्फ मोदी के चेहरे की बदौलत जीतने का जो प्रयास कर रहा है वह भाजपा के लिए काफी महंगा साबित हो सकता है।

अपने लाख प्रयास के बावजूद मोदी सरकार अभी तक इस्लामी आतंकवाद की कमर तोड़ने में सफल नहीं हुई है। हाल ही में आईएसआईएस से जुड़े कुछ आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, जोकि 'गजवा-ए-हिंद' मिशन के तहत 2047 तक हिंसा के जरिए भारत में इस्लामी हुकूमत को पुनर्स्थापित करने की तैयारी कर रहे थे। खास बात यह है कि जो आरोपी पकड़े गए हैं वे उच्च शिक्षा प्राप्त हैं। सरकार ने भले ही पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगा दिया हो, लेकिन उसकी गतिविधियां गुप्त रूप से बदस्तूर जारी हैं। हाल ही में गुप्तचर एजेंसियों ने पॉपुलर फ्रंट के नेटवर्क को तबाह करने के लिए देश के नौ राज्यों के दो दर्जन से अधिक स्थानों पर छापेमारी की थी और 'गजवा-ए-हिंद' से संबंधित काफी साहित्य और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए थे।

देश के मुस्लिम नेता और उनके सेक्युलर समर्थक भले ही इस्लामी एकता का बेसुरा राग अलापते रहें, मगर हकीकत यह है कि मुस्लिम देश ही एक दूसरे को तबाह व बर्बाद करने के प्रयासों में जी जान से लगे हुए हैं। हाल ही में तुर्किये की संसद पर प्रतिबंधित शिया संगठन पीपुल्स डिफेंस फोर्सेस के आतंकियों ने हमला किया। इससे पहले भी तुर्किये को इस्लामी आतंकी अपना निशाना बनाते रहे हैं। तुर्किये के रक्षा मंत्री ने यह दावा किया है कि तुर्किये की संसद पर हमला करने वालों के तार सीरिया से जुड़े हुए हैं और उन्हें वहां के गुप्त शिविरों में आतंकवाद का प्रशिक्षण दिया गया था। गौरतलब है कि सीरिया और कुर्द दोनों ही शिया हैं। जबकि तुर्किये एक सुन्नी देश है।

पाकिस्तान सरकार ने पाकिस्तान में रह रहे 40 लाख अफगान नागरिकों में से 20 लाख को अगले महीने के प्रारंभ तक देश से निष्कासित करने की घोषणा की है। पाकिस्तान के गृह मंत्री ने दावा किया कि ये लोग अवैध रूप से वर्षों से पाकिस्तान में रह रहे हैं और इनके तार तस्करों और आतंकियों से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान सरकार के इस फैसले का अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने विरोध किया है। तालिबान सरकार के अधिकृत प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान सरकार क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ कोई कार्रवाई करने में विफल रही है, इसलिए वह अब अफगान नागरिकों को अपना निशाना बना रही है ताकि उसकी विफलता पर पर्दा डाला जा सके।

इस्लामिक आतंकियों के मकड़जाल में भारत

इंकलाब (3 अक्टूबर) के अनुसार दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने आतंकी संगठन आईएसआईएस से संबंधित तीन आतंकियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में इंजीनियर शाहनवाज आलम उर्फ अब्दुल्ला, मौलाना मोहम्मद रिजवान अशरफ और मोहम्मद अरशद वारसी शामिल हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ बरामद किया है। दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त एचजीएस धालीवाल का कहना है कि गुप्तचर एजेंसियां लंबे समय से आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन और आईएसआईएस से जुड़े हुए लोगों पर नजर रखी हुई थी। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने इन आतंकी संगठनों से जुड़े हुए अनेक गिरोहों का पता लगाया है। इस गिरोह का संबंध कोल्हापुर, सांगली और सतारा से भी था। उन्होंने दावा किया कि पिछले महीने ही दिल्ली पुलिस ने इन आतंकियों की गिरफ्तारी के लिए ईनाम की भी घोषणा की थी। इन पर अनेक बम धमाके करने का आरोप है।

जब इन आतंकियों के ठिकाने पर छापेमारी की गई तो भारी मात्रा में बम बनाने का सामान बरामद किया गया। धालीवाल का कहना है कि मौलाना मोहम्मद रिजवान को लखनऊ से, मोहम्मद अरशद वारसी को मुरादाबाद से और शाहनवाज को दिल्ली के जैतपुर से गिरफ्तार किया गया है। शाहनवाज की गिरफ्तारी पर तीन लाख का इनाम घोषित किया गया था। कुछ समय पहले शाहनवाज पुणे पुलिस की हिरासत से फरार हो गया था। शाहनवाज के कब्जे से अवैध हथियार और बम बनाने का सामान बरामद हुआ है। इन आतंकियों को बम बनाने का सामान पाकिस्तान में बैठे इनके आकाओं ने उपलब्ध करवाया था। शाहनवाज झारखंड के हजारीबाग का रहने वाला है। उसने बेंगलुरु के विश्वेश्वरय्या इंस्ट्टियूट ऑफ टेक्नोलॉजी से माइनिंग इंजीनियरिंग की है और उसे

बम बनाने की भी पूरी जानकारी है। बेंगलुरु में शाहनवाज ने एक हिंदू लड़की बसंती पटेल को अपने जाल में फंसाया था और शादी के बाद इस्लाम में धर्मांतरण करवाकर उसका नाम खदीजा मरियम रखा गया।

वहीं, मोहम्मद अरशद वारसी भी झारखंड का रहने वाला है और उसने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। इस समय वह जामिया मिलिया इस्लामिया से पीएचडी कर रहा है। मौलाना मोहम्मद रिजवान अशरफ उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का रहने वाला है और उसने गाजियाबाद से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बीटेक किया है।

रोजनामा सहारा (5 अक्टूबर) के अनुसार राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने अपनी जांच में यह पाया है कि कि शाहनवाज आलम और रिजवान अपने छात्रकाल से ही आईएसआईएस की विचारधारा से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने आईएसआईएस से जुड़े हुए विभिन्न ट्विटर अकाउंट और अन्य सोशल मीडिया को फॉलो करना शुरू कर दिया था। इसके अतिरिक्त वे झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कई मुस्लिम युवकों को आईएसआईएस के स्लीपर सेल के तौर पर भर्ती भी किया करते थे। पुलिस का दावा है कि अक्षरधाम मंदिर पर हमले का आरोपी फरहतुल्लाह उनका रोल माडॅल था। शाहनवाज आलम अपने पांच भाई बहनों में सबसे बड़ा है। उसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हजारीबाग के मशहूर पब्लिक स्कूल सेंट जेवियर से प्राप्त की थी। इसके बाद वह कोटा चला गया था और बाद में उसने नागपुर से बीटेक किया था। दिल्ली में रहते हुए वह कट्टरवादी इस्लामिक लॉबी के संपर्क में आया था।

इसी समाचारपत्र में प्रकाशित एक अन्य समाचार के अनुसार आतंकी संगठन आईएसआईएस से संबंध रखने के आरोप में पकड़े गए रिजवान अशरफ की गिरफ्तारी के बाद देश की खुफिया एजेंसियों ने आजमगढ़ की ओर विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि इससे पूर्व भी आजमगढ़ से संबंध रखने वाले अनेक आतंकियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट, मुंबई बम धमाका, वाराणसी धमाका, टी-सीरीज कंपनी के मालिक गुलशन कुमार की हत्या और बाटला हाउस एनकाउंटर केस में भी आजमगढ़ से जुड़े हुए अनेक आतंकियों के नाम सामने आए थे। पिछले वर्ष आजमगढ़ के सबाउद्दीन आजमी को भी गिरफ्तार किया गया था। पिछले तीस सालों में देश में जहां भी आतंकी धमाके हुए हैं उनके तार किसी न किसी रूप में आजमगढ़ से जुड़े हुए पाए गए हैं। अभी तक इस जिले से संबंधित तीन दर्जन से अधिक आतंकियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से कई लोग एनकाउंटर में मारे भी गए हैं। जबकि कई जेलों में बंद हैं।

12 मार्च 1993 में मुंबई में हुए सीरियल बम धमाकों में ढ़ाई सौ से अधिक लोग मारे गए थे। इस संदर्भ में अबू सलेम और अब्दुल कयूम अंसारी का नाम सामने आया था, जोकि इस समय उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। ये दोनों आजमगढ़ के सराय मीर के रहने वाले हैं। मुंबई जाने के बाद अबू सलेम अंडरवर्ल्ड डॉन दाउद इब्राहिम के नजदीक आया था और 1997 में टी-सीरीज के मालिक गुलशन कुमार को दाउद के इशारे पर उसने गोली मारकर हत्या कर दी थी। हाल ही में इस मामले की सुनवाई मुंबई उच्च न्यायालय में हुई थी और न्यायालय ने इन आरोपियों को जमानत पर रिहा करने से इंकार कर दिया था।

अवधनामा (12 अक्टूबर) के अनुसार बिहार के फुलवारी शरीफ के पॉपुलर फ्रंट से जुड़े आतंकियों की तलाश में देश भर के 20 स्थानों पर छापे मारे गए। इन छापों में गजवा-ए-हिंद के तहत 2047 तक देश में इस्लामी शासन स्थापित करने से संबंधित तैयारियों के बारे में महत्त्वपूर्ण दस्तावेजें बरामद हुई हैं। एनआईए ने 2022 में इस मामले की जांच शुरू की थी और अब तक इस मामले में 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दिल्ली के ओखला और शाहीन बाग के छह स्थानों पर छापे मारे गए। एनआईए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गुप्तचर सूत्रों से इस बात की जानकारी मिली थी कि पॉपुलर फ्रंट दिल्ली में होने वाले जी-20 सम्मेलन के दौरान धमाके करने की तैयारी कर रहा था। उन्होनें कहा कि इस गिरोह से जुड़े हुए लोगों की तलाश में पुलिस ने फजलपुर, शाहीन बाग, ओखला, चांदनी चौक, भोपाल, मुंबई, ठाणे, टोंक, श्रीगंगानगर, लखनऊ, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, संत रविदास नगर और कानपुर के साथ-साथ तमिलनाडु के मदुरै में भी छापे मारे। इन छापों के दौरान काफी संख्या में लैपटॉप, मोबाइल फोन, सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क भी बरामद किए गए हैं। इन छापों में साढ़े आठ लाख रुपये नकद भी बरामद हुए हैं, जोकि विदेशी स्रोतों से इस संगठन को प्राप्त हुए थे। इस अधिकारी के अनुसार पहली बार इस गिरोह का सुराग बिहार के फुलवारी शरीफ में मारे गए छापों के दौरान मिला था। अब तक गजवा-ए-हिंद के सिलसिले में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें अतहर परवेज, मोहम्मद जलालुद्दीन खान, नूरुद्दीन, अरमान मलिक उर्फ इम्तियाज अनवर आदि शामिल हैं। इस गिरोह का संबंध प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिमी से भी पाया गया है। इस गिरोह का सरगना अनवर राशिद है, जो एक पब्लिशिंग हाउस की आड़ में अपनी गतिविधियां चला रहा था।

मुंबई उर्दू न्यूज (12 अक्टूबर) के अनुसार मानवाधिकारों के पक्ष में आवाज उठाने वाले अब्दुल वाहिद शेख के घर पर एनआईए ने छापा मारा। यह व्यक्ति मुंबई बम धमाकों का भी आरोपी था। जेल में रहने के दौरान उसने एक किताब 'बेगुनाह कैदी' भी लिखी है। शेख ने जब छापा मारने वालों से उनके पहचान पत्र मांगे तो उन्होंने उसे दिखाने से इंकार कर दिया। जब उसने आईएनए से तलाशी वारंट मांगा तो वह भी एनआईए के पास नहीं था। इसके बाद एनआईए के लोग जबरन दरवाजा तोड़कर वाहिद शेख के घर में घुस गए। फिर शेख के वकील इब्राहिम हर्बट भी वहां पहुंच गए और उन्होंने छापा मारने वालों से लीगल नोटिस मांगा, जिस पर एनआईए ने उन्हें कुछ कागज दिखाए। लेकिन इब्राहिम हर्बट ने इन कागजों को स्वीकार करने से मना कर दिया। अब्दुल वाहिद शेख ने मुंबई उर्दू न्यूज को बताया कि हालांकि बम धमाकों के केस से वह बरी हो चुका है, इसके बावजूद सरकारी एजेंसियां उसे जानबूझकर परेशान कर रही हैं। उसने हाल ही में इशरत जहां एनकाउंटर पर भी एक किताब लिखी है। समाचारपत्र ने दावा किया है कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद देश के हर उस मुसलमान को तबाह व बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, जो मुसलमानों में इस्लाम और

उनके नागरिक अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करता है।

उर्दू टाइम्स (13 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि चुनाव की धमक शुरू होते ही खुफिया एजेंसियां फिर से सक्रिय हो गई हैं। जगह-जगह छापे मारे जा रहे हैं और इन छापों का निशाना सिर्फ मुसलमानों को बनाया जा रहा है। हम नहीं जानते कि ऐसा क्यों किया जा रहा है? लेकिन मुसलमानों को आईएसआईएस से जोड़कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस आरोप में कितनी सच्चाई है यह या तो जांच एजेंसियां जानें या सत्ता में बैठे लोग, जिनके इशारे पर यह सब हो रहा है। एनआईए ने हाल ही में देश में 20 से अधिक स्थानों पर छापे मारे हैं। क्या जांच हो रही है इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मुंबई में मानवाधिकारों के लिए आवाज उठाने वाले अब्दुल वाहिद शेख के घर पर सुबह पांच बजे छापा मारना क्या जायज है? उन्हें अदालत आतंकवाद के आरोप से बरी कर चुकी है। उन्होंने मुसलमानों में जागृति पैदा करने और उन्हें उनके कानूनी अधिकारों के बारे में अवगत कराने के लिए देश भर में जो अभियान छेड़ रखा है, उससे सरकार और जांच एजेंसियां परेशान हैं। अगर जांच एजेंसयों को उनके घर की तलाशी लेनी थी तो उनके पास पहचान पत्र और सर्च वारंट होने चाहिए। वे अपनी पहचान क्यों छिपा रहे थे? स्थानीय पुलिस ने आंख बंद करके उनका साथ क्यों दिया? इस तरह के अनेक प्रश्न हैं, जिनका जवाब कौन देगा?

समाचारपत्र का कहना है कि क्या मुसलमान अब इस देश में इज्जत से भी नहीं रह सकते? गरीबी की जिंदगी गुजारने वाले मुसलमानों को क्या पड़ी है कि वे आईएआईएस से संबंध रखें। यह तो जांच एजेंसियों का कारनामा है कि वे बेगुनाह लोगों को गैर-कानूनी तरीके से गिरफ्तार करती हैं। मुसलमानों को सालों जेल में रखा जाता है और जब जांच एजेंसियां अदालत में उनके खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं कर पातीं तो उन्हें रिहा कर दिया जाता है। मगर जिन लोगों ने बेगुनाह लोगों को वर्षों जेल में रखा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। हम तो यही समझ रहे हैं कि इन जांच एजेंसियों और खास तौर पर एनआईए को इसलिए सक्रिय किया गया है ताकि वह सत्ता में आए गिरोह के बारे में मुसलमानों में भय पैदा करे और वे चुनाव में हिस्सा न लें।

मुस्लिम नेताओं के निशाने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

अवधनामा (2 अक्टूबर) में ओबैदुल्लाह नासिर का एक लेख प्रकाशित हुआ है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि आरएसएस हिंदू धर्म और हिंदुस्तान के स्वरूप को बदलने का प्रयास कर रहा है। नासिर ने अपने लेख की शुरुआत एक शेर से की है, 'एक दो जख्म नहीं सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे'। लेखक ने अपने लेख में आरोप लगाया है कि पिछले दस सालों से हिंदुस्तानी मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं और उनका जीना दूभर किया जा रहा है। कदम-कदम पर उन्हें देश से अलग करने का प्रयास किया जा रहा है और यह एक दर्दनाक कहानी है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले इस देश में सब बढ़िया था। दंगे होते रहे और उसने हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों की जानें लीं। खरबों रुपये की संपत्ति को आग के हवाले किया गया। सरकारी नौकरियों में मुसलमानों का अनुपात तेजी से गिरता चला गया। लेकिन कुछ ऐसी भी बातें थीं, जिससे आशा की किरण पैदा होती थी। पहली तो यह कि चंद हजार दंगाईयों के मुकाबले में लाखों हिंदू मुसलमानों के समर्थन में खड़े होते थे। समाज में धर्म के आधार पर

विभाजन और मुसलमानों से इतनी गहरी नफरत इससे पहले कभी नहीं थी। पुरानी सरकारें कभी खुलकर मुस्लिम दुश्मनी का प्रदर्शन नहीं करती थीं।

लेखक का कहना है कि 2014 से पहले और बाद के हिंदुस्तान को देखिए तो दोनों में आकाश पाताल का साफ फर्क दिखाई देगा। यहां तक कि सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, बल्कि हिंदू धर्म भी बदल गया है। अगर न बदला होता तो गणेश चतुर्थी के पंडाल से एक केला उठाकर खा लेने वाले मानसिक रूप से विकलांग एक मुस्लिम नौजवान को खंभे से बांधकर इतना न पीटा जाता कि उसकी मौत हो जाए। यह खबर पढ़कर मुझे विख्यात कवि स्वर्गीय खुर्शीद अफसर की एक आप बीती की याद आ गई। उन्होंने लिखा है कि बचपन में मैं और मेरा दोस्त अक्सर गांव के मंदिर से प्रसाद चुरा लेते थे। हम दोनों पकड़े गए। पुजारी के सामने हमारी पेशी हुई। उन्होंने घटना को सुना और फिर उन्होंने हमारे सिर पर हाथ फेरा। हमें पकड़कर ले जाने वालों को उन्होंने डांटते हुए कहा कि भगवान का प्रसाद था। बाल भगवानों ने अगर खा लिया तो इसमें परेशान होने की क्या बात है।

इसी तरह से अयोध्या की एक घटना का उल्लेख करते हुए पत्रकार स्वर्गीय लाइक अख्तर ने लिखा था कि अयोध्या के कुछ मनचले एक मुस्लिम विधवा की जवान लड़की से छेड़खानी करते थे। तंग आकर वह विधवा बड़े महंत जी के पास गई और उन्हें पूरी घटना से अवगत कराया। महंत जी ने तुरंत अपने कुछ चेलों को भेजकर उन मनचलों को पकड़वाया और उनकी जमकर पिटाई कर दी। फिर उस विधवा से कहा कि बेटी तुम जल्दी से जल्दी अपनी बेटी की शादी कर दो। विधवा ने कहा कि वह आर्थिक रूप से बहुत गरीब है। महंत जी ने कहा कि तुम रिश्ता तय करो, शादी मंदिर की तरफ से होगी। मगर अब तो जमाना ही बदल गया है। आरएसएस के चिंतक गुरु गोलवलकर ने अपनी पुस्तक 'वी ओर आवर नेशनहुड डिफाइंड' में इस देश के तीन अंदरूनी दुश्मन मुसलमान, ईसाई और कम्युनिस्ट को बताए हैं। वे देश में इन्हें कोई संवैधानिक अधिकार देने के समर्थक नहीं थे। मूल रूप से वे संविधान विरोधी भी थे। उनका कहना था कि ऋषि-मुनियों द्वारा रचित मनुस्मृति जब हमारे पास है तो हमें किसी नए संविधान की क्या जरूरत है?

लेखक का कहना है कि 2013 तक भारत संविधान के तहत चलता रहा। लेकिन 2014 के बाद मोदी का युग शुरू होते ही सब कुछ बदल गया। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब मुल्क के किसी न किसी हिस्से में मामूली बातों को लेकर मुसलमानों और ईसाइयों पर हमला न किया जाता हो। बजरंग दल के लंपट धर्म ध्वजा लेकर खुदाई फौजदार बन चुके हैं और कानून की रक्षक पुलिस या तो उनके साथ शामिल हो जाती है या मूकदर्शक बनी रहती है। ऐसे में अगर कोई अधिकारी कानून के अनुसार कार्रवाई करता है तो हुकूमत पूरी बेशर्मी के साथ उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करती है जैसा अभी बरेली के पुलिस कप्तान के साथ किया गया।

देश की संसद के नए भवन में भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी ने जो कुछ किया उससे नए हिंदुस्तान की झलक मिलती है। रमेश बिधूड़ी द्वारा आरएसएस ने यह संदेश दे दिया कि संसद के अंदर भी मुसलमानों की इज्जत और आबरू सुरक्षित नहीं है। हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है इससे दुनिया भर के मुसलमान बेखबर नहीं हैं। इस तरह से जो हिंदू धर्म दुनिया में सबसे उदार धर्म माना जाता था, वह कट्टरपंथ के शिकंजे में फंसा हुआ है। भगवान राम के नाम पर वह सब कुछ हो रहा है जो उनकी शिक्षाओं, आदर्शों और मर्यादाओं के सरासर खिलाफ है।

इंकलाब (9 अक्टूबर) ने आदिल अफरोज का एक लेख प्रकाशित किया है, जिसमें कहा गया है कि यह कड़वी सच्चाई है कि आजाद

हिंदुस्तान में कभी भी मुसलमानों को उनका जायज हक नहीं दिया गया। मगर हम सेक्युलर रहे। मुसलमानों को खुशफहमी में फंसाए रखने के लिए उन्हें कुछ पद भी थमा दिए गए। पिछले कुछ सालों में भगवा संगठन के नफरत भरे एजेंडे को जिस तरह से प्रशासकीय स्तर पर प्रोत्साहन दिया गया है उसे भुलाया नहीं जा सकता। वह हिंदुस्तान जिसे स्वर्ग कहा जाता था, नर्क में बदल दिया गया है। धार्मिक जुलूसों पर तो हमले हमेशा होते रहे हैं। लेकिन कभी मजहब और आस्था की आजादी पर डाका नहीं डाला गया। अब तो मुसलमानों की पहचान पर ही हमला किया जा रहा है। नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। बच्चों को स्कूलों में नफरत का पाठ पढ़ाया जा रहा है। भगवा संगठनों की शाखाएं पूरे देश में फैली हुई हैं। इन शाखाओं का प्रशासन पर पूरा कब्जा है। प्रशासन को यह भी साहस नहीं होता कि वह किसी भी आरोप के बारे में भगवा संगठनों से जुड़े हुए लोगों की जांच करें या उन्हें गिरफ्तार करें। सरकारी और गैर-सरकारी कर्मचारी इन शाखाओं के सदस्य होते हैं।

लेखक का कहना है कि भारतीय इतिहास को गलत ढंग से पेश किया जा रहा है, जिसके कारण स्कूलों में धार्मिक नफरत की भावना तेजी से बढ़ रही है। पिछले साल कई मुस्लिम चिंतकों ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की थी। मोहन भागवत ने उन्हें विश्वास दिलाया था कि मुसलमानों के खिलाफ मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं हो रही हैं, उन्हें रोका जाएगा। लेकिन जमीनी स्तर पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। बाद में इन चिंतकों और बुद्धिजीवियों ने एक बयान जारी करके कहा कि मोहन भागवत की कथनी और करनी में भारी अंतर है।

इंकलाब (9 अक्टूबर) में प्रकाशित एक लेख में मुस्लिम चिंतक मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी ने यह आरोप लगाया है कि यह प्रयास किया जाता है कि मुसलमानों की समस्याओं का असल हल निकालने की बजाय उसके रूख को गलत दिशा में मोड़ दिया जाए। यह सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि सच्चाई पर पर्दा पड़ा रहे और असली मामले से लोगों का ध्यान हट जाए। के. आर. मलकानी जैसे हिंदूवादी चिंतक काफी सोच विचार करने के बाद इस परिणाम पर पहुंचे थे कि समस्याओं के समाधान के लिए यह जरूरी है कि मुसलमानों से गहरा संपर्क स्थापित किया जाए। इसलिए मुसलमानों की ओर से इस बात का प्रयास किया गया कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच के संबंधों को सुधारा जाए। अब भी कई मुस्लिम संगठनों जैसे जमीयत उलेमा-ए-हिंद, जमात-ए-इस्लामी, मिल्ली काउंसिल और जमीयत अहले हदीस की ओर से कुछ लोगों ने आरएसएस के सामने अपनी बातों को रखते हुए आपसी संबंधों को सुधारने का काम किया है। लेकिन आरएसएस की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई गंभीर कदम नहीं उठाया गया है। हालांकि, पिछले कुछ दिनों में सरसंघचालक मोहन भागवत के कई बयान मुसलमानों से नजदीकी और आपसी संबंधों को सुधारने के बारे में सामने आए थे। लेकिन इन बयानों को पूरा करने में संघ प्रमुख अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं। इस ओर जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने भी इशारा किया है। उन्होंने डॉ. मोहन भागवत और आरएसएस के रूख व भूमिका की आलोचना करते हुए कहा है कि आरएसएस ने सांप्रदायिक सौहार्द के बारे में हमसे जो वायदे किए थे, वह उनसे पीछे हट गया है।

मुंबई उर्दू न्यूज (13 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि कभी मोहन भागवत कहते हैं कि इस देश में रहने वाले तमाम मुसलमान भी हिंदू हैं। कभी वे कहते हैं कि बस उपासना का तरीका अलग है, वरना हम सभी एक हैं। उनका सब एक होने का अर्थ यह है कि हम सब सिर्फ हिंदू हैं। हाल ही में देश की राजधानी दिल्ली में एक समारोह को संबोधित करते हुए

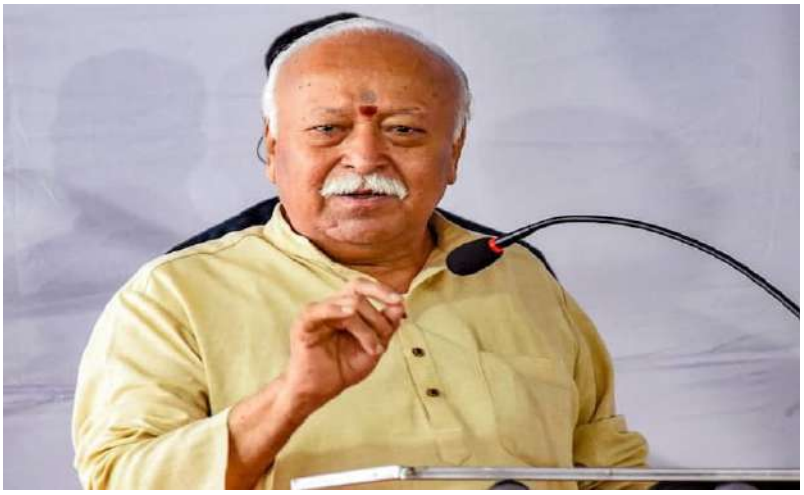

मोहन भागवत ने कहा, 'हिंदुस्तान दुनिया को यह सिखाता है कि विविधता में एकता नहीं, बल्कि एकता की ही विविधता है'। अगर भागवत के इस वाक्य को डिकोड किया जाए तो इसका मतलब भी वही निकलता है, जो वे एक लंबे अरसे से कहते चले आ रहे हैं कि इस देश में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं। इस देश को आरएसएस के संस्थापकों ने एक हिंदू राष्ट्र के तौर पर देखा है, इसलिए वे कभी भी अनेकता में एकता के नारे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनके अनुसार सभी लोग हिंदू हैं। इसका एक मतलब यह भी है कि विभिन्न धर्मों के जो अलग-अलग धाराएं हैं, उनका उद्गम स्थल एक ही है और वह है हिंदू धर्म। लेकिन यह सच नहीं है। सच यही है कि इस देश में बेशुमार धर्म हैं। सैकड़ों जातियां हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम सब हिंदुस्तानी हैं। यह हिंदू और हिंदुस्तानी का फर्क है। भागवत इसे मिटाने के लिए काफी समय से प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसे मिटाना संभव नहीं है।

समाचारपत्र का कहना है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातिगत सर्वे की रिपोर्ट को पेश करके पूरी भगवा मंडली को बौखलाहट में धकेल दिया है। उच्च जाति के हिंदू 15 प्रतिशत से भी कम हैं। 85 प्रतिशत ओबीसी, ईबीसी और अन्य लोगों की है, जिनमें मुसलमान भी शामिल हैं और वे बिहार की आबादी का 17 प्रतिशत हैं। अब भागवत बेचैन हैं कि यह जो विभिन्न जातियां अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो रही हैं या खड़ी हो सकती हैं, उन्हें किस तरह से अपने साथ मिलाया जाए। इसलिए उन्होंने यह नया शिगूफा छोड़ा है। लेकिन सब जान रहे हैं कि यह फरेब से भरा हुआ नारा सिर्फ सत्ता पर काबिज होने के लिए लगाया जा रहा है। सब लोग यह भी जानते हैं कि आरएसएस ने कभी भी पिछड़े वर्ग के कल्याण की बात नहीं की है। अगर की भी तो उसका कारण राजनीति रही है। जब मंडल का युग आया तो कमंडल को आगे बढ़ाने के लिए उसने बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के विवाद को तेज किया और ओबीसी सहित सभी पिछड़ों को भी हिंदुत्व की धारा में समेटकर बाबरी मस्जिद को शहीद करवा दिया। मस्जिद की शहादत ने आरएसएस के राजनीतिक विंग भाजपा को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचा दिया।

तासीर (15 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि सत्ता को हथियाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने गैर-हिंदुओं को भाजपा के करीब लाने के लिए अभियान छेड़ दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा खास तौर पर खानकाहों और दरगाहों को आबाद करने वाले सूफी मुसलमानों को अपने कैंप में लाने का प्रयास कर रही है। इस अभियान की बागडोर भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चे को दी गई है। इस संदर्भ में 150 सूफियों को जोड़ा गया है। ये लोग उत्तर प्रदेश के हर जिले में जाकर भाजपा के नेताओं से बातचीत करेंगे और उनके परामर्श से इस काम को आगे बढ़ाएंगे। इस अभियान को चलाने के लिए

उत्तर प्रदेश भाजपा कार्यालय में इन सूफी मुसलमानों और अल्पसंख्यक मोर्चे के पदाधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। उन्हें बताया गया है कि वे अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से सूफियों के प्रति श्रद्धा रखने वाले मुसलमानों के बीच कैसे जाएंगे और उन्हें कैसे बताएंगे कि भाजपा ने अल्पसंख्यकों के लिए क्या-क्या किया है।

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली का कहना है कि इस अभियान में मुस्लिम उलेमा और सूफी मुसलमानों को शामिल किया जाएगा। भाजपा के प्रति मुसलमानों के दिलो दिमाग में जो भ्रांति फैली हुई है उसे ये लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। मुसलमानों को यह भी बताया जाएगा कि भाजपा की राज्य और केंद्र सरकार मुसलमानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए क्या-क्या कर रही है और वह किस तरह से अपने कल्याणकारी योजनाओं के जरिए मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाना चाहती है। उनका यह भी कहना है कि इस अभियान को चलाने के पीछे का लक्ष्य यह है कि भाजपा की विचारधारा को सूफी मुसलमानों तक पहुंचाया जाए। इस अभियान में अजमेर शरीफ और निजामुद्दीन औलिया दरगाह के लोगों को भी साथ में लिया गया है। भाजपा लगभग एक हजार मजारों और दरगाहों तक पहुंचेगी।

भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी का कहना है कि भाजपा सभी अल्पसंख्यकों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। सूफियों से वार्ता का अभियान मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में चलाया जाएगा। इन क्षेत्रों में सेमिनार आयोजित किए जाएंगे। इस लक्ष्य से लोकसभा के उन क्षेत्रों को चुना गया है जहां मुसलमानों की आबादी 20 प्रतिशत या उससे अधिक है। इस अभियान के तहत मुस्लिम समुदाय के लोगों के घर-घर पहुंचकर उनसे बातचीत की जाएगी। दरगाहों पर कव्वालियों का आयोजन किया जाएगा। भाजपा का मानना है कि दरगाहों और मजारों पर जाने वाले अल्पसंख्यक समुदाय को केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं से सबसे ज्यादा लाभ होता है। क्योंकि इनमें से अधिकांश लोग पिछड़े वर्ग से संबंध रखते हैं। पार्टी का यह भी मानना है कि 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में आठ प्रतिशत मुसलमानों ने भाजपा को वोट दिए थे। रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में भाजपा को जीत दिलाने में मुसलमानों का विशेष योगदान रहा है।

बाटला हाउस एनकाउंटर केस के आरोपी को उच्च न्यायालय से राहत

उर्दू टाइम्स (13 अक्टूबर) के अनुसार बाटला हाउस एनकाउंटर केस में दिल्ली की साकेत अदालत ने मुख्य आरोपी आरिज खान को फांसी की सजा दी थी, जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय ने अब उम्र कैद में बदल दिया है। गौरतलब है कि 2008 में हुए इस मुठभेड़ में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 2021 में इस केस का फैसला साकेत अदालत ने सुनाया था और उसने आरिज खाान को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। आरिज खान उर्फ जुनैद एक दशक तक फरार रहा। 2018 में उसे दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली उच्च न्यायालय के जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अमित शर्मा की खंडपीठ ने फांसी की सजा को चुनौती देने वाली अपील पर अपना फैसला सुनाया है।

गौरतलब है कि एडिशनल सेशन जज संदीप यादव ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 186, 333, 353, 302, 397 और आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत दोषी करार दिया था। फांसी की सजा सुनाते हुए अदालत ने कहा था कि सरकारी वकील ने इस केस से संबंधित जो दस्तावेज और वैज्ञानिक प्रमाण प्रस्तुत किए हैं उससे यह साबित होता है कि आरिज खान ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की सरकारी कार्यवाही में रूकावट डाली और उनकी हत्या की। अदालत ने यह स्वीकार किया था कि एक वर्दीधारी पुलिस की हत्या करना 'रेयरेस्ट ऑफ द रेयर' की श्रेणी में आता है इसलिए दोषी को फांसी की सजा दी जाती है।

उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अपने 105 पन्नों के फैसले में माना है कि आरिज खान आतंकी गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल था। वह उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा था। लेकिन इसी बीच वह गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल लोगों के संपर्क में आया और आतंकी बन गया। खंडपीठ ने कहा है कि यह मुठभेड़ पूर्वनियोजित

नहीं थी। दिल्ली में पांच स्थानों पर हुए बम धमाकों की जांच के सिलसिले में एक संदिग्ध आरोपी की तलाश में दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के नेतृत्व में बाटला हाउस के फ्लैट नंबर एल 18 पर पहुंची तो अंदर से गोलीबारी शुरू हो गई। इंस्पेक्टर मोहन चंद को कई गोलियां लगीं। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। वहीं दो आतंकियों को पुलिस ने मौके पर ही मार गिराया। जबकि एक आतंकी शहजाद कुछ घंटे बाद ही पुलिस के गिरफ्त में आ गया। आरिज खान वहां से फरार हो गया। उसे 14 फरवरी 2018 को गिरफ्तार किया गया। साकेत अदालत ने 8 मार्च 2021 को आरिज को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई थी और उस पर 11 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था।

खंडपीठ ने कहा है कि हम आरोपी को सुधरने का मौका देना चाहते हैं। खंडपीठ ने कहा कि एक उच्च शिक्षा प्राप्त 23 वर्षीय युवक बहक सकता है। ऐसे में उसे जेल के सलाखों के पीछे रखकर ही सुधारने का प्रयास किया जा सकता है। खंडपीठ ने कहा है कि ऐसे कई बिंदु सामने आए हैं जिससे इस बात की पुष्टि नहीं होती है कि इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा को जो गोली लगी है, वह आरिज खान ने ही चलाई थी। हालांकि, खंडपीठ ने यह माना है कि वह आतंकी है, इसलिए उसे हत्यारा मानना उचित है।

गौरतलब है कि 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में पांच स्थानों पर बम धमाके हुए थे, जिनमें 39 लोग मारे गए थे। 19 सितंबर को दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा को यह जानकारी मिली कि कुछ संदिग्ध आतंकी बाटला हाउस में छिपे हुए हैं। हालांकि, पुलिस को यह जानकारी नहीं थी कि इस फ्लैट में पांच आरोपी छिपे हुए हैं। शहीद पुलिस इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की पत्नी माया शर्मा ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा आरिज खान की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलने पर हैरानी जताई है और कहा है कि इस फैसले से दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों के मनोबल पर बुरा असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सत्र अदालत ने यह माना था कि यह रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामला है। ऐसी स्थिति में क्या उसकी फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलना उचित होगा? माया शर्मा ने कहा कि वह इस मामले को सर्वोच्च में चुनौती देने पर विचार कर रही हैं।

पांच राज्यों के चुनाव और मुसलमान

सियासत (13 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि देश के पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के मतदान का दिन जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, विभिन्न राजनीतिक दल समाज के विभिन्न वर्गों को रिझाने और उनका समर्थन करने का प्रयास कर रहे हैं। जहां तक भाजपा का सवाल है वह तो देश के पांच राज्य हों या पूरे देश में चुनाव हों, मुसलमानों को महत्व देने के लिए कतई तैयार नहीं है। शायद ही किसी राज्य में किसी मुस्लिम उम्मीदवार को भाजपा की ओर से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। भाजपा धीरे-धीरे मुसलमानों को राजनीति से दूर करने की नीति को कार्यान्वित कर रही है। इस नीति का किसी राज्य में उसे लाभ भी हुआ तो किसी राज्य में उसे नुकसान का भी सामना करना पड़ा है। इस पूरे खेल में सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि मुसलमानों में राजनीतिक जागरूकता कितनी है। मुसलमानों में यह भावना उत्पन्न होनी चाहिए कि कौन उनका राजनीतिक इस्तेमाल करके शोषण कर रहा है और उनको बलि का बकरा बनाते हुए खुद सत्ता की मलाई चाट रहा है।

समाचारपत्र का कहना है कि मुसलमानों के बारे में यह आम राय होती जा रही है कि वे किसी पार्टी या उम्मीदवार का पूर्ण समर्थन नहीं करते। चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर तेलंगाना हो मुसलमानों को एक सुनियोजित राजनीति तय करनी चाहिए। मुसलमानों ने पहले उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सूझबूझ और राजनीतिक जागरूकता का प्रदर्शन करते हुए जब अपने वोटों का सामूहिक रूप से इस्तेमाल किया था तो वहां पर भाजपा को करारी हार हुई थी और समाजवादी पार्टी सत्ता में आ गई थी। बात केवल उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है। जहां-जहां मुसलमानों ने एकजुट होकर अपने वोटों का इस्तेमाल किया, वहां अवसरवादी और सांप्रदायिक ताकतों को मुंह की खानी पड़ी। इससे राजनीति में मुसलमानों के महत्व में वृद्धि हुई। इसलिए यह जरूरी है कि मुसलमान इस बार भी

सामूहिक रूप से किसी एक पार्टी को, जो भाजपा को हरा सकती हो को वोट दें।

इस संबंध में यह बात भी विचारणीय है कि इन पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव इन राज्यों तक ही सीमित नहीं रहने वाले हैं, बल्कि इनका प्रभाव आने वाले संसदीय चुनाव पर भी पड़ेगा। मुसलमान चाहे जिस भी पार्टी का समर्थन करें, लेकिन उन्हें यह जरूर विचार करना चाहिए कि वे जिस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, कहीं उसके तार भाजपा से जुड़े हुए तो नहीं हैं। पुराने रिकॉर्ड भी देखे जाने चाहिए कि किस पार्टी ने किन-किन मौकों पर भाजपा का सीधे या परोक्ष रूप से समर्थन किया था। जो लोग ऐसी पार्टियों का समर्थन करने के लिए मुसलमानों से अपील करें उनसे यह सवाल जरूर किया जाना चाहिए कि क्या वे अपने व्यक्तिगत हितों के कारण पूरी कौम के साथ सौदेबाजी तो नहीं कर रहे हैं?

समाचारपत्र ने कहा है कि मुसलमानों को ऐसी रणनीति अपनानी चाहिए, जिसके आधार पर उनके प्रतिनिधित्व में वृद्धि हो सके और उन्हें समाज में जायज स्थान मिल सके। मुसलमानों की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति में सुधार हो सके और उन्हें विकास में भी उचित भागीदारी मिल सके। आज समाज का हर तबका विकास के फलों को प्राप्त करने के लिए अपनी हिस्सेदारी पर जोर दे रहा है। वे अपने अधिकारों के लिए भी संघर्षशील हैं। मुसलमानों को भी अपने जायज हिस्सेदारी को प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दूरदर्शिता और सूझबूझ के साथ एक व्यापक रणनीति अपनाने की जरूरत है। सिर्फ भावुक बनने या परंपराओं की गुलामी करने से उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा। अगर उन्हें अपनी हालात को बदलना है तो उन्हें अपने आप को तैयार करना होगा। मुसलमानों को हमेशा यह बात याद रखनी चाहिए कि कोई अपने व्यक्तिगत स्वार्थ या राजनीतिक मजबूरियों के लिए भाजपा का साथ देने और साथ लेने के लिए तैयार न हो जाए। भविष्य में जो खतरे हमारे सामने आ सकते हैं उन्हें समय रहते ही समझ लेना चाहिए और उसे देखते हुए अपनी रणनीति तय करनी चाहिए। संविधान और कानून के दायरे में रहते हुए अपने वोटों द्वारा ऐसी ताकतों को पराजित करने से गुरेज नहीं करना चाहिए, जो अपने स्वार्थों के लिए फिरकापरस्तों के हाथों का खिलौना बनते हैं। यह स्वर्णिम अवसर है कि मुसलमान सामूहिक रूप से अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता का प्रदर्शन इन राज्यों के चुनावों में करें।

उर्दू टाइम्स (13 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि पांच राज्यों के चुनावों ने घमासान मचा दिया है। भाजपा यह चुनाव केंद्रीय नेतृत्व और एक व्यक्ति के बलबूते पर लड़ने जा रही है और हमेशा की तरह चुनाव के सभी महत्त्वपूर्ण फैसले भाजपा हाईकमान ने अपने हाथों में ले रखे हैं। इस नीति से विभिन्न राज्यों के नेता परेशान हैं, मगर वे कुछ भी करने की स्थिति में नहीं हैं। लेकिन राजस्थान में मामला ऐसा नहीं है। मोदी-शाह की जोड़ी ने जिस तरह से हर राज्य में वहां के नेतृत्व को हाशिए पर कर दिया है, उसी तरह से राजस्थान में भी किया है। दो बार मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे सिंधिया की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हद तो यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अभी तक अपने किसी भी भाषण में वसुंधरा राजे का नाम तक नहीं लिया है और न ही उनके शासनकाल की किसी भी योजना का ही कोई उल्लेख किया है।

समाचारपत्र का कहना है कि चुनावी मंचों पर वसुंधरा राजे की उपेक्षा की जा रही है। किस उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा, उसकी बागडोर भी हाईकमान ने अपने हाथ में ले रखी है। भाजपा पहली बार मुख्यमंत्री के चेहरे की चर्चा किए बिना मैदान में उतर रही है। पार्टी का यही रवैया वसुंधरा राजे एवं उनके समर्थकों को पसंद नहीं आ रहा है। भाजपा ने उम्मीदवारों की पहली सूची में वसुंधरा राजे के किसी भी समर्थक को टिकट नहीं

दिया है। इसके विरोध स्वरूप वसुंधरा राजे खुलकर मैदान में आ गई हैं और पार्टी हाईकमान के साथ दो-दो हाथ करने के मूड में हैं। वसुंधरा राजे गुट के 25 उम्मीदवारों ने स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। केंद्र में मोदी के सत्ता में आने के बाद यह पहला मौका है जब राजस्थान का सबसे बड़ा नेता हाईकमान के सामने खुलकर मैदान में आ गया है। राजनीतिक गलियारों में चल रही चर्चा के अनुसार वसुंधरा राजे अपने 52 समर्थकों को निर्दलीय मैदान में उतारने का इशारा दे चुकी हैं। प्रदेश की राजनीति को वसुंधरा भलीभांति समझती हैं और वहां की राजनीति पर उनकी मजबूत पकड़ है। उनके वफादारों की भी लंबी कतारें हैं। वसुंधरा राजे पूरी तरह से बगावत के मूड में हैं और उनका लक्ष्य चुनाव जीतने से ज्यादा भाजपा को पराजित करने का होगा।

हमारा समाज (11 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि अगले महीने होने वाले पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में भाजपा का सीधा मुकाबला कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा करके 'भारत जोड़ो' का जो अभियान चलाया है, उसका आम लोगों में भारी असर हुआ है। समाचारपत्र का कहना है कि राहुल गांधी की यह नीति असल में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की इस नीति के खिलाफ है, जिससे संघ परिवार देश को टुकड़े-टुकड़े करना चाहता है और हिंदुओं व मुसलमानों को आपस में लड़ाकर अनादि काल तक सत्ता की मलाई चाटने का स्वप्न देख रहा है।

समाचारपत्र का कहना है कि कांग्रेस ने दूसरा कदम यह उठाया है कि 28 पार्टियों को मिलाकर आईएनडीआईए गठबंधन की रचना की है। इस गठबंधन से भाजपा बेहद परेशान है। राहुल गांधी ने संसद और संसद के बाहर ओबीसी का मुद्दा बहुत ही जोर शोर से उठाया है। भाजपा कई राज्यों में सत्तारूढ़ है। लेकिन सिर्फ एक राज्य में उसका मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग से संबंधित है और उसकी भी जल्द ही छुट्टी होने वाली है।

इत्तेमाद (1 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि तेलंगाना में विधानसभा चुनाव करीब है। लेकिन भाजपा की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। उसके नेताओं के आपसी मतभेद के कारण पार्टी के कार्यकर्ताओं में वह जोश नहीं है जो कुछ महीने पहले तक दिखाई दे रहा था। हैदराबाद पर कब्जे के दिवस के सिलसिले में जब गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद का दौरा किया तो उनकी जनसभा में ज्यादातर खाली कुर्सियां थीं, जोकि तेलंगाना में भाजपा की कमजोर स्थिति का प्रमाण है।

हमारा समाज (15 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में यह भविष्यवाणी की है कि पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में आईएनडीआईए गठबंधन मजबूती से अपनी मौजूदगी दर्ज करवा पाएगा। अभी तक तो हालत यह रही है कि विपक्षी गठबंधन से जुड़ी पार्टियां भाजपा के सामने घिघियाने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर पाई हैं। मोदी सरकार की कथनी और करनी के फर्क को

अभी तक वह जनता के सामने सफलतापूर्वक पेश नहीं कर सकी हैं। नतीजा यह है कि भाजपा मोदी और शाह के नेतृत्व में कामयाबी की सरपट दौड़ लगाती आ रही है और विपक्ष अपने वजूद को जनता से कबूल करवाने में भी विफल रही है। सवाल यह है कि कर्नाटक में कांग्रेस को जो विजय प्राप्त हुई थी, क्या उसे इन चुनावों में विपक्षी दल दोहरा पाने में सफल हो पाएंगे? अभी तक भाजपा हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में लड़ाकर सत्ता में रही है।

यह हकीकत है कि 2014 में भ्रष्टाचार को महत्त्वपूर्ण मुद्दा बना कर भाजपा ने यूपीए सरकार का खात्मा कर दिया था। लेकिन भाजपा के शासनकाल में भी न तो भ्रष्टाचार का अंत हुआ और न ही जनता को किसी भी तरह की सुविधा मिली। वर्तमान शासनकाल में भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई है और जनता महंगाई की चक्की में बुरी तरह से पीस रही है। मगर भाजपा ने नफरत को कुछ इस तरह से बढ़ावा दिया है कि जनता उसकी विफलताओं और अपनी परेशानियों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रही है।

सालार (1 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने यह दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी लोकतंत्र के बेहतरीन ब्रांड बन चुके हैं और परिवारवाद का खात्मा करके वह ग्राउंड जीरो के विश्व हीरो भी बन जाएंगे। हमें नकवी के इन जुमलों को सुनकर बड़ी हैरानी हुई है। मोदी सरकार ने जिस तरह से उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल और राज्यसभा की सदस्यता से वंचित किया है उससे शायद उनके आत्मसम्मान पर चोट लगी होगी। लेकिन उन्होंने जिस तरह से मोदी को लोकतंत्र का मसीहा करार देकर उनकी तारीफ के पुल बांधने की कोशिश की है, उससे अंदाजा कुछ और ही हो रहा है। हिंदुस्तान पिछले नौ सालों में विश्व भर में लोकतंत्र, अभिव्यक्ति व प्रेस की आजादी और हंगर इंडेक्स में जिस तरह से नीचे गिरकर आ रहा है वह बिगड़ती हुई स्थिति की ओर साफ संकेत करता है। खुद को विश्वगुरु कहने वाले मोदी ने लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। जिस खामोशी से इस देश के संविधान से सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म को खारिज किया जा रहा है, उसके बाद भी मोदी को लोकतंत्र का ब्रांड करार दिया जाए तो ऐसा लोकतंत्र हमारी समझ से बाहर है।

तासीर (2 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि लोकसभा के चुनाव के लिए विपक्षी दलों ने आईएनडीआईए नामक जिस गठबंधन का गठन किया है, उसका ऊंट कब किस करवट बैठेगा उसके बारे में अनुमान लगाना मुश्किल हो रहा है। ऐसा इसलिए है कि बिहार में एक बार फिर से दबी जुबान यह आवाज उठने लगी है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार जैसे सामाजिक और राजनीतिक सुझबूझ वाले व्यक्ति को होना चाहिए। दूसरी ओर, कांग्रेस की नजर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर लगी हुई है। हालांकि, नीतीश कुमार बार-बार यह कह चुके हैं कि वे प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं। मगर जब से जनता दल (यूनाइटेड) और आरजेडी एक बार फिर से एक साथ आए हैं, तब से आरजेडी द्वारा नीतीश को प्रधानमंत्री बनाने की मांग का

समर्थन किया जा रहा है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता भाई वीरेन्द्र का कहना है कि प्रधानमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार सबसे योग्य व्यक्ति हैं।

वहीं, कांग्रेस के महासचिव तारिक अनवर का कहना है कि स्वयं नीतीश कुमार कई बार यह कह चुके हैं कि वे प्रधानमंत्री पद के लिए इच्छुक नहीं हैं। अगर आईएनडीआईए गठबंधन सत्ता में आता है तो चुनाव के बाद यह फैसला होगा कि देश का प्रधानमंत्री किसे बनाया जाए। आईएनडीआईए की गाड़ी पंजाब में फंसती हुई दिखाई दे रही है। वहां पर हाल ही में कांग्रेस एमएलए सुखपाल सिंह खैरा को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है, उससे आम आदमी पार्टी की सरकार और कांग्रेस के बीच टकराव शुरू हो गया है।

सियासत (2 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद इन राज्यों में भाजपा की मुश्किलें तेजी से बढ़ रही हैं। राजस्थान में कांग्रेस के फिर से सत्ता में आने की संभावना बढ़ गई है। यही कारण है कि सभी राज्यों में स्थानीय नेतृत्व को नजरअंदाज करके भाजपा सिर्फ नरेन्द्र मोदी के नाम पर ही वोट मांग रही है। मध्य प्रदेश में हालात कर्नाटक जैसे हो गए हैं और भाजपा के कई नेता कांग्रेस का दामन थामने लगे हैं। भाजपा विभिन्न राज्यों में पार्टी के अंदर चल रहे अंतर्द्वंद्व को भलीभांति समझती है इसलिए वह सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ही वोट लेना चाहती है। भाजपा को सिर्फ दो व्यक्तियों और एक चेहरे तक ही सीमित करने की कोशिश की जा रही है। यही प्रयास हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में किया गया था, जो विफल रहा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार को जनता का समर्थन प्राप्त है और वहां पर अभी तक भाजपा अपना रंग जमाने में सफल नहीं हो सकी है। इसी तरह से तेलंगाना में भी भाजपा तीसरे या चौथे स्थान पर चली गई है। वहां पर चुनावी मुकाबला कांग्रेस और बीआरएस के बीच रह गया है। मिजोरम में होने वाले चुनाव पर भी मणिपुर की घटनाक्रम का प्रभाव पड़ सकता है।

इत्तेमाद (10 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि तेलंगाना में बीआरएस की विपक्षी पार्टियों के गठबंधन से सीधी टक्कर है। चंद्रशेखर राव अपनी सफलता के बारे में इतने आश्वस्त हैं कि उन्होंने चुनावी तिथि की घोषणा होने से पहले ही राज्य विधानसभा के 119 सीटों में से 115 पर नामों की घोषणा कर दी थी।

अखबार-ए-मशरिक (9 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि भाजपा और आरएसएस हाईकमान अपने स्थानीय नेतृत्व को जिस तरह से नजरअंदाज करके मनमानी कर रहा है, वह इन राज्यों में भाजपा की हार का कारण बनेगा।

उर्दू अखबारों के निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी

हमारा समाज (11 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इजरायल का समर्थन करने के बारे में जो बयान दिया है वह बुद्धिमता का काम नहीं है। हैरानी की बात यह है कि हमारे देश भारत में भी यह आवाजें उठने लगी हैं कि इजरायल भी भारत की तरह एक पीड़ित देश है, जिस पर फिलिस्तीन पाकिस्तान की तरह आतंकी कार्रवाईयां कर रहा है। इसलिए भारत ने इजरायल के साथ खड़े होने की घोषणा की है। अब अगर इस सिद्धांत को एक तरफ कर भी दें तो हम प्रधानमंत्री मोदी से पूछना चाहते हैं कि दरअसल पीड़ित देश कौन सा है? प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर कहा है कि इजरायल में हुए आतंकी हमले से उन्हें भारी धक्का लगा

है। हमारी दुआएं इजरायल के साथ हैं और इस मुश्किल घड़ी में हम इजरायल के साथ खड़े हैं। लेकिन यह बयान देने से पहले प्रधानमंत्री से यह भी न हो सका कि वे फिलिस्तीन और इजरायल के विवाद पर इस्लामोफोबिया से ऊपर उठकर देखने की कोशिश करते। उन्हें यह भी अंदाजा नहीं हुआ कि मुसलमानों और इस्लाम से नफरत का जो बारूद उन्होंने बिछाया हुआ है, उनके बोलते ही उनके पालतू चेले इसमें इतनी तिलियां लगाएंगे कि इस आग पर वे खुद भी काबू नहीं पा पाएंगे।

समाचारपत्र का कहना है कि हमास और इजरायल की जंग को भारतीय जनता पार्टी मुख्य मुद्दा बनाना चाहती है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हमास के हमले को इजरायल पर आतंकी हमला करार दिया है और कहा है कि उनकी सरकार इजरायल के साथ खड़ी है। नरेन्द्र मोदी की यह नीति पुरानी सरकार से बिल्कुल अलग है। कांग्रेसी सरकारें तो निरंतर फिलिस्तीनियों का समर्थन करती आ रही हैं। यहां तक कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भी फिलिस्तीन के पक्ष में बयान दिए थे और इजरायल से फिलिस्तीन के अधिकृत क्षेत्रों को खाली करने की बात कही थी। हमास से नरेन्द्र मोदी का अभिप्राय मुसलमान है और इजरायल मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। जैसे संघ परिवार हिंदुस्तान में मुसलमानों की दुश्मनी में सबसे आगे हैं। वैसे ही इजरायल अरब देशों और दुनिया भर के मुसलमानों के लिए दुश्मन नंबर एक है। यही कारण है कि नरेन्द्र मोदी हिंदू भाईयों को खुश करने के लिए हिंदू-मुस्लिम मामले को चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं। फिलिस्तीन एक पीड़ित देश है। हमास मुसलमानों और फिलिस्तीनियों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है। अरब देशों के शासक भले ही खुले तौर पर नरेन्द्र मोदी के मुंह पर कुछ नहीं बोलते। लेकिन अरब देशों की जनता मोदी सरकार की नीतियों से खुश नहीं हैं।

समाचारपत्र ने कहा है कि प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी के लोग जो अपने आप को विदेश नीति का विशेषज्ञ मानते हैं उन्हें इस मुद्दे की

गंभीरता का उतना भी अंदाजा नहीं था, जितना किसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर या किसी अखबार के संपादक को होता है। जामिया मिलिया इस्लामिया के एक प्रोफेसर का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह भावना जागृत की गई है कि सिर्फ मुसलमान ही आतंकी हो सकता है और दूसरा कोई आतंकी नहीं हो सकता है। इसी भावना से भारत सरकार भी ग्रस्त है। यहां पर यह याद रखना भी महत्त्वपूर्ण है कि जब हम इजरायल और फिलिस्तीन पर बात करते हैं तो हम बुनियादी विवाद को भूल जाते हैं। हम इस बात को भूल जाते हैं कि इजरायल ने अरबों की जमीन पर कब्जा किया है। दुर्भाग्य से अरब देशों के अंदर भी यह भावना जन्म लेने लगी है कि अब फिलिस्तीन को छोड़कर इजरायल के साथ रिश्ते जोड़े जाएं। हम फिलिस्तीनी जनता को यह संदेश देना चाहते हैं कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है और तुम अकेले हो। यह तुम्हारी अपनी लड़ाई है, लड़ो या बिना लड़े तबाह हो जाओ। अगर अरब देश ईमानदारी का सबूत नहीं देते तो इस बात की भी संभावना है कि अरब देशों की जनता अपने शासकों के ही खिलाफ मैदान में आ जाए। जहां तक भारत का संबंध है तो इसके वर्तमान प्रमुख नरेन्द्र मोदी ने इजरायल के साथ खड़े होने की घोषणा करके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख को भारी धक्का पहुंचाया है।

उर्दू टाइम्स (11 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि किसी भी देश की विदेश नीति उस देश के अंदर रहने वाली जनता की भावनाओं को समक्ष रखकर ही बनाई जाती है। लेकिन हमारे देश की बात ही निराली है। यहां सत्ता में बैठे लोग अपने मन मुताबिक नीतियां बनाते हैं। यही कारण है कि आधे से ज्यादा दुनिया ने अभी इजरायल को मान्यता नहीं दी है। फिर भी भारत उसे मान्यता दे चुका है। कांग्रेस के शासनकाल में सरकार संभल-संभलकर चलती थी। मगर मोदी सारकार ने तो खुलेआम इजरायल की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है। यही कारण है कि पिछले दिनों जब हमास ने इजरायल पर अचानक हमला कर दिया तो इजरायल से खुलेआम हमदर्दी में सबसे पहले दो ही देश आगे आए और वे हैं अमेरिका और भारत। अमेरिका की तो मजबूरी थी। मगर भारत मजबूर नहीं था। भारत को यह अच्छी तरह से मालूम है कि इजरायल ने फिलिस्तीन पर कितना जुल्म ढाया है। फिलिस्तीन के दो टुकड़े करने में इजरायल के साथ अमेरिका खड़ा रहा। गाजा के मुसलमानों पर जुल्मो सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। गाजा के इन पीड़ितों के समर्थन में सिर्फ हमास खड़ा हुआ और आज वह ताकतवर हो रहा है, जिसे आज चंद मुल्क आतंकी संगठन का नाम दे रहे हैं। जबकि इजरायल से बड़ा आतंकी कौन है? इसके बावजूद कुछ देश उसे आतंकी नहीं मानते। इजरायल जासूसी के मामले में पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा रहा है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का अभियान चलाने वाले संगठन 'अभिनव भारत' का मुख्यालय भी इजरायल के तेल अवीव में है।

समाचारपत्र का कहना है कि हमें हमास के खिलाफ प्रधानमंत्री के बयान पर आपत्ति है। प्रधानमंत्री मोदी को निहत्थे मासूम बच्चों की चीखें सुनाई नहीं दी, जिन्हें इजरायल की जालिम फौज ने गोलियों से भून दिया। पूरे गाजा की नाकेबंदी कर दी गई है। रॉकेटों के हमले जारी हैं। इमारतों को खंडहर में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद न जाने क्यों भारत इजरायल के साथ खड़ा है। अगर सारे अरब मुल्क इजरायल पर थूक दें तो यह मुल्क बह जाएगा। मगर न जाने किस मजबूरी की वजह से अरब मुल्क खामोश हैं और यहां तक कि वे इजरायल से राजनयिक संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इजरायल का जुर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। मस्जिद अल-अक्सा में मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है। छोटे-छोटे निहत्थे बच्चों को मारा जा रहा है। इससे मजबूर होकर हमास ने यह

कदम उठाया है। लेकिन अब इजरायल बौखलाकर मासूम मुसलमानों पर हमला कर रहा है और इसे रोकने की जरूरत है।

अखबार-ए-मशरिक (12 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में नरेन्द्र मोदी द्वारा इजरायल का समर्थन किए जाने की आलोचना की है और कहा है कि भारत सरकार ने पीड़ित फिलिस्तीनियों का समर्थन करने की बजाय आक्रांता इजरायल का समर्थन करके एक गलत उदाहरण पेश किया है। भाजपा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि उसने हमास के आतंकी हमले की निंदा न करके मुसलमानों को रिझाने का काम किया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने अपने ट्विट में कहा है कि 'जब कांग्रेस आतंकवाद का समर्थन कर रही है तो वह भारत में आतंकवाद को कैसे रोक सकती है?'

इंकलाब (12 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में भारत सरकार से आग्रह किया है कि फिलिस्तीन-इजरायल विवाद पर जो उसने स्टैंड लिया है उस पर उसे पुनर्विचार करना चाहिए। अब से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि हमने फिलिस्तीन पर इजरायल को प्राथमिकता दी हो। आजादी के बाद से अब तक हर सरकार फिलिस्तीन का समर्थन करती आ रही है और सभी सरकारों ने इजरायली आक्रामकता की निंदा की है।

सहाफत (12 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि नरेन्द्र मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को टेलीफोन करके जो आश्वासन दिया है कि भारत इजरायल के साथ खड़ा है, उसका कोई समर्थन नहीं कर सकता। इसलिए भारत सरकार को इस मामले में अपनी नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए और इस बात पर जोर देना चाहिए कि फिलिस्तीन की समस्या को बातचीत के जरिए हल किया जाए।

अखबार-ए-मशरिक (11 अक्टूबर) के अनुसार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों ने प्रदर्शन करके भारत सरकार की इजरायल समर्थक नीति का विरोध किया है और फिलिस्तीनी जनता का समर्थन किया है। समाचारपत्र का कहना है कि दिल्ली पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा भी दर्ज किया है। जबकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के चार छात्र नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

इंकलाब (14 अक्टूबर) ने मुख्य समाचार के रूप में एक समाचार प्रकाशित करके कहा है कि देश भर की मस्जिदों में फिलिस्तीनी मुसलमानों की कामयाबी के लिए खास दुआएं की गई हैं और इजरायल के हमले की निंदा की गई है। दिल्ली के जंतर मंतर, हैदराबाद, कश्मीर, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में मुसलमानों ने जगह-जगह फिलिस्तीनी मुसलमानों के पक्ष में प्रदर्शन किए हैं और इजरायली हमले की निंदा की है।

एक अन्य समाचार के अनुसार दारूल उलूम देवबंद के प्रमुख अबुल कासिम नोमानी ने प्रधानमंत्री मोदी से अनुरोध किया है कि वे अपनी विदेश नीति पर पुनर्विचार करें और इजरायल की निंदा करें।

इंकलाब (13 अक्टूबर) के अनुसार जमात-ए-इस्लामी, जमीयत उलेमा-ए-हिंद, मुस्लिम मजलिस-ए-मुशावरत और वेल्फेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने भारत सरकार से मांग की है कि वह फिलिस्तीन और इजरायल के विवाद के मामले में अपनी नीति पर पुनर्विचार करे। क्योंकि वर्तमान नीति भारतीय जनता के हित में नहीं है।

इंकलाब (13 अक्टूबर) के अनुसार विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि फिलिस्तीन के मसले पर भारत अपनी पुरानी नीति पर कायम है। भारत हमेशा वार्ता द्वारा एक आजाद और स्वशासी फिलिस्तीन की स्थापना का वकालत करता आ रहा है और अब भी हम उसी पुरानी नीति पर कायम हैं।

लाखों अफगानों के पाकिस्तान से निष्कासन से तनाव

पाकिस्तान सरकार ने पाकिस्तान में रहने वाले लाखों अफगान नागरिकों को देश से निष्कासित करके जबरन अफगानिस्तान भेजने का जो फैसला किया है, उसके कारण दोनों देशों के संबंधों में जबर्दस्त तनाव पैदा हो गया है।

उर्दू टाइम्स (4 अक्टूबर) के अनुसार पाकिस्तान सरकार ने यह फैसला किया है कि उनके देश में जो विदेशी नागरिक अवैध रूप से रह रहे हैं, उन्हें इस महीने के अंत तक जबरन उनके देशों में भेज दिया जाएगा। इस फैसले का सबसे ज्यादा प्रभाव पाकिस्तान में रहने वाले अफगान नागरिकों पर पड़ेगा। पाकिस्तान में अवैध रूप से रहने वाले विदेशी नागरिकों को उनके मूल देशों में भेजने का फैसला उच्चस्तरीय बैठक में लिया गया है।

पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर ने संवाददाताओं को बताया कि 31 अक्टूबर तक सभी विदेशी नागरिकों को उनके देशों में वापस भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो विदेशी नागरिक पाकिस्तान में रह रहे हैं उन्हें एक महीने के भीतर अपनी संपत्तियों को बेचना होगा, वरना उनकी सभी अचल संपत्तियों को पाकिस्तान सरकार जब्त कर लेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सिर्फ पंजीकरण का प्रमाण रखने वाले अफगान नागरिकों को ही पाकिस्तान में रहने का अधिकार होगा। उन्होंने कहा कि 31 अक्टूबर के बाद पुलिस और अर्धसैनिक बल देश भर में अवैध रूप से रहने वाले विदेशी नागरिकों की गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू कर देंगे। एक नवंबर के बाद कोई भी अफगान नागरिक बिना पासपोर्ट और वीजा के पाकिस्तान की सीमा में दाखिल नहीं हो सकेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि जो पाकिस्तानी इन विदेशी नागरिकों को शरण और आवास की सुविधाएं प्रदान करेंगे उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि काफी अफगान नागरिक जाली पहचान पत्रों के आधार

पर पाकिस्तान में रह रहे हैं। पाकिस्तान सरकार की गुप्तचर एजेंसियों को यह निर्देश दिया गया है कि वे ऐसे विदेशी नागरिकों का सुराग लगाएं और उन्हें गिरफ्तार करें। उन्होंने कहा कि यह कदम पाकिस्तान में बढ़ती हुई आतंकी घटनाओं और तस्करी के कारण लिया गया है।

इंकलाब (13 अक्टूबर) के अनुसार पाकिस्तान सरकार ने पाकिस्तान में रहने वाले अफगान नागरिकों की गिरफ्तारियों का सिलसिला तेज कर दिया है, ताकि उन्हें निर्धारित समय से पहले उनके देश भेजा जा सके। गैर-सरकारी सूत्रों के अनुसार अब तक 10 हजार से अधिक अफगान नागरिकों को जबरन उनके देश भेजा जा चुका है।

इत्तेमाद (5 अक्टूबर) के अनुसार अफगान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान सरकार को धमकी दी है कि वह अफगान नागरिकों को जबरन निष्कासित करने के फैसले पर पुनर्विचार करे, वरना उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने इस बात का खंडन किया कि अफगान नागरिक आतंकी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि ये अफगान नागरिक सदियों से पाकिस्तान में रह रहे हैं। इसलिए उन्हें जबरन निष्कासित करने का फैसला अनुचित है। पाकिस्तान सरकार को उन्हें बर्दाश्त करना चाहिए। जब उनकी मर्जी होगी तभी वे पाकिस्तान से बाहर जाएंगे। पाकिस्तान के गृह मंत्री सरफराज बुगती ने दावा किया है कि इस वर्ष देश में हुए अधिकांश आत्मघाती हमलों में अफगान नागरिकों का हाथ पाया गया है। उन्होंने कहा कि इस समय पाकिस्तान में 17-18 लाख अफगान नागरिकों के पास कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है। उन्होंने दावा किया कि इस समय पाकिस्तान में कुल 44 लाख अफगान रह रहे हैं। पिछले कई दशक से अफगानिस्तान में जो अशांति का माहौल है, उसके कारण पाकिस्तान सरकार ने मानवीय आधार पर इन अफगान नागरिकों को देश में दाखिल होने की अनुमति दी थी।

हमारा समाज (6 अक्टूबर) के अनुसार पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के प्रमुख नेता फरहतुल्लाह बाबर ने पाकिस्तान सरकार पर आरोप लगाया कि ये अफगान शरणार्थी एक त्रि-सूत्रीय समझौते के तहत पाकिस्तान में रह रहे हैं और आने वाले चुनावों में पाकिस्तानियों के वोट बटोरने के लिए अफगान नागरिकों को सत्तारूढ़ दल देश से निष्कासित कर रहा है। इस्लामाबाद में स्थित अफगान दूतावास ने पंजाब और सिंध पुलिस पर यह आरोप लगाया है कि वह गैर-कानूनी तौर पर लाखों अफगान नागरिकों को गिरफ्तार कर रही है और उन्हें उनके घरों से बेदखल कर रही है। हालांकि, उनके पास पाकिस्तान में रहने के कानूनी दस्तावेज भी मौजूद हैं।

इसी समाचारपत्र में प्रकाशित एक अन्य समाचार के अनुसार पाकिस्तान सरकार ने पारगमन व्यापार समझौते के तहत 212 तरह की वस्तुओं को पाकिस्तान से अफगानिस्तान ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें 17 तरह का कपड़ा, वाहनों के टायर और पुर्जे, चाय की पत्ती, सौंदर्य और शौचालय में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं को पाकिस्तान से अफगानिस्तान ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अतिरिक्त जिन अन्य वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें फल, रेफ्रिजरेटर, एसी, मिक्सर ग्राइंडर आदि

शामिल हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों चमन सीमा पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों में गोलीबारी हुई थी, जिसमें कुछ लोग मारे गए थे।

हमारा समाज (8 अक्टूबर) के अनुसार अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने अफगान शरणार्थियों को पाकिस्तान से निष्कासित करने के फैसले की निंदा की है और कहा है कि इससे दोनों देशों के संबंध और ज्यादा खराब होंगे। उन्होंने अफगान नागरिकों को यह भी निर्देश दिया है कि वे पाकिस्तान में पूंजी निवेश करना बंद कर दें।

मालदीव चीन की गोद में

मुंबई उर्दू न्यूज (8 अक्टूबर) के अनुसार हिंद महासागर में स्थित मालदीव में हुए आम चुनाव में चीन समर्थक मोहम्मद मुइज्जू राष्ट्रपति चुने गए हैं। गौरतलब है कि 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मालदीव में भारत विरोधी ताकतों के बढ़ते हुए हस्तक्षेप को रोकने के लिए भारतीय नौसेना को वहां पर भेजा था और भारत समर्थक मौमून अब्दुल गयूम की सत्ता की रक्षा की थी। मालदीव में 98 प्रतिशत आबादी सुन्नी मुसलमानों की है। हालांकि, इस देश में लगभग 1200 टापू हैं, लेकिन लगभग 200 टापुओं में लोगों की बसावट है। पाकिस्तान और चीन काफी समय से मालदीव में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।

गौरतलब है कि इससे पहले भी मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति और चीन के प्रबल समर्थक अब्दुल्ला यामीन ने चुनाव में सफलता प्राप्त की थी। मगर जनता ने विद्रोह करके उनकी सरकार का तख्ता पलट दिया था। इसके बाद भारत समर्थक इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के सत्ता में आने के बाद भारत के साथ मालदीव के संबंधों में सुधार हुआ था। मोहम्मद मुइज्जू विपक्षी नेता के रूप में मालदीव की भारत के साथ दोस्ती का विरोध करते रहे हैं। चीन मालदीव के साथ अपने संबंधों को बढ़ाना चाहता है। इस समय मालदीव के व्यापारिक संबंध मुख्य रूप से भारत के साथ है। समाचारपत्र ने दावा किया है कि मालदीव में चीन समर्थकों के सत्ता में आने के कारण भारत के हितों को जबर्दस्त चोट पहुंचने की संभावना है।

इत्तेमाद (6 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में आने के बाद पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध दिन-प्रतिदिन खराब हो रहे हैं। नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश के बाद अब चीन ने मालदीव में भी भारी मात्रा में पूंजी निवेश करने की घोषणा की है। समाचारपत्र ने दावा किया है कि भारत विरोधी मोहम्मद मुइज्जू ने 'इंडिया आउट' के आधार पर चुनाव लड़ा था और उन्हें भारत के समर्थक राष्ट्रपति मोहम्मद सोलिह को हराने में सफलता मिली है। समाचारपत्र ने दावा किया है कि मालदीव की जनता में

आर्थिक कारणों से भारत के खिलाफ भावना उभर रही थी, जिसका मोहम्मद मुइज्जू की पार्टी प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव ने फायदा उठाया। मोहम्मद सोलिह की पार्टी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी को भीतरघात के कारण और पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद के विरोध के कारण सत्ता से हाथ धोना पड़ा है।

हमारा समाज (6 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में यह दावा किया है कि मालदीव में चीन समर्थकों की जीत के कारण भारत को आने वाले समय में जबर्दस्त परेशानी होगी। क्योंकि चीन वहां पर अपना नौसैनिक अड्डा स्थापित कर सकता है। इसके कारण मालदीव में रह रहे भारतीय सेना के सलाहकारों को बोरिया-बिस्तर बांधना होगा। चीन ने हाल ही में मालदीव में भारी पूंजी निवेश करने की घोषणा की है। उसने मालदीव की राजधानी को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से मिलाने वाले एक पुल का निर्माण भी किया है। मालदीव के चीन समर्थक पुराने शासकों ने उसे एक द्वीप 2016 में लीज पर दिया था, जिस पर चीन अपना नौसैनिक अड्डा बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही मालदीव को चीन ने एक बिलियन डॉलर कर्ज देने की घोषणा की है। नए राष्ट्रपति ने यह घोषणा की है कि भारतीय सेना के जो सलाहकार मालदीव में रह रहे हैं, उन्हें उनके देश वापस भेज दिया जाएगा। मोहम्मद मुइज्जू ने ब्रिटेन से उच्च शिक्षा प्राप्त की है। मालदीव का बहुसैनिक महत्व है। अगर वहां पर चीन का प्रभाव बढ़ा तो उससे हिंद महासागर में भारत की स्थिति बेहद कमजोर हो जाएगी।

ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त को गुरुद्वारे में जाने से रोका गया

अवधनामा (3 अक्टूबर) के अनुसार ब्रिटेन स्थित भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोरईस्वामी जब ग्लासगो के एक गुरुद्वारे में जाने का प्रयास कर रहे थे तो उन्हें खालिस्तान समर्थकों ने गुरुद्वारे में दाखिल होने से रोक दिया और उनकी कार को भी क्षति पहुंचाने का प्रयास किया। समाचारपत्रों के अनुसार इस भीड़ में पाकिस्तानी और खालिस्तानी दोनों ही शामिल थे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस बात का प्रचार किया गया था कि स्कॉटलैंड निवासी एक सिख ब्लॉगर जगतार सिंह जोहल को भारत सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके अतिरिक्त कनाडा में रहने वाले एक खालिस्तानी की हत्या के पीछे भी भारत की एक गुप्तचर एजेंसी के हाथ होने के आरोप के कारण भी इस क्षेत्र में काफी नाराजगी थी।

भारतीय दूतावास के सूत्रों के अनुसार ग्लासगो में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों ने भारतीय उच्चायुक्त को बातचीत करने के लिए इस

गुरुद्वारे में आमंत्रित किया था। मगर प्रदर्शनकारियों ने उन्हें गुरुद्वारे में प्रवेश करने से रोक दिया। बताया जाता है कि इन प्रदर्शनकारियों में अधिकांश स्थानीय निवासी नहीं थे और न ही वे भारतीय मूल के लोग थे। इस घटना के पीछे पाकिस्तानी गुप्तचर एजेंसी का हाथ होने का भी आरोप लगाया गया है। भारत सरकार ने इस संबंध में ब्रिटेन की सरकार से विरोध प्रकट किया है और यह मांग की है कि ब्रिटेन स्थित भारतीय उच्चायोग और उसके कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान की जाए। ब्रिटेन के उप विदेश मंत्री ने इस घटना

पर चिंता प्रकट की है और कहा है कि ब्रिटेन सरकार सभी विदेशी दूतावासों और उसके कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि उपासना स्थलों में किसी भी व्यक्ति को दाखिल होने से रोकना सरासर गलत है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन की मीडिया में भारत सरकार के खिलाफ कुछ झूठी खबरें प्रकाशित हुई थीं, जिनके कारण भारतीय मूल के निवासियों में भारी नाराजगी थी और उन्होंने हकीकत जानने के लिए भारतीय उच्चायुक्त और भारतीय वाणिज्य दूत को गुरुद्वारे में बुलाया था। मगर कुछ शरारती तत्वों ने उनकी कार को रोक दिया और उन्हें गुरुद्वारे में दाखिल होने से जबरन रोका। इसके बाद भारतीय उच्चायुक्त बिना गुरुद्वारे में दाखिल हुए और बिना किसी से बातचीत किए वापस लौट गए। स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है कि वहां पर एक गुरुद्वारे में प्रदर्शन होने के बारे में उन्हें सूचना प्राप्त हुई थी। स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस पूरी घटना की जांच कर रही है। ब्रिटेन में लगभग पांच लाख सिख रहते हैं और स्कॉटलैंड में भी एक लाख के लगभग सिख रहते हैं।

बताया जाता है कि हाल ही में स्कॉटलैंड निवासी एक सिख ब्लॉगर जगतार सिंह जोहल की गिरफ्तारी के मामले में वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा था। जगतार सिंह पिछले कुछ सालों से भारतीय जेल में बंद है। उसके खिलाफ हिंदू संगठनों के नेताओं की हत्या की साजिश करने और आतंकी घटनाओं में भाग लेने का आरोप है। गौरतलब है कि हाल ही में कनाडा में एक खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के कारण भारत और कनाडा के संबंधों में भी काफी तनाव पैदा हो गया है। भाजपा के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि अतिवादियों की यह हरकत निंदनीय है, क्योंकि गुरुद्वारे में हर व्यक्ति को जाने का अधिकार है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी इस घटना की निंदा की है और उसके महासचिव गुरचरण सिंह ग्रेवाल ने कहा है कि गुरुद्वारे में भारतीय उच्चायुक्त को जाने से रोकना निंदनीय और सिख परंपरा के खिलाफ है।

पाकिस्तान में आतंकी घटनाओं में वृद्धि

रोजनामा सहारा (1 अक्टूबर) के अनुसार अफगान सरकार ने पाकिस्तान के चित्राल क्षेत्र में हुए आत्मघाती बम धमाकों के सिलसिले में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के 200 से अधिक आतंकियों को गिरफ्तार किया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने अफगान जनता को निर्देश दिया है कि वे किसी भी आतंकी संगठन को कोई सहायता प्रदान न करें। गौरतलब है कि पाकिस्तान सरकार की ओर से बार-बार यह आरोप लगाया जाता है कि अफगानिस्तान की भूमि का इस्तेमाल पाकिस्तान में हिंसक गतिविधियों की तैयारी करने के लिए किया जा रहा है। इसी साल के 6 सितंबर को पाकिस्तान के चित्राल जिले में पाकिस्तान और अफगान सीमा पर स्थित दो सैनिक चौकियों पर प्रतिबंधित संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों ने हमला किया था, जिसमें 12 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। आतंकियों ने पाकिस्तानी सेना की इन चौकियों से अस्त्र-शस्त्र भी लूट लिए थे। पाकिस्तानी सेना की जवाबी कार्रवाई में 20 आतंकियों के मारे जाने का दावा किया गया था।

इंकलाब (10 अक्टूबर) के अनुसार बलूचिस्तान के झोब जिले में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन के दौरान पांच आतंकी मारे गए जबकि पाकिस्तानी सेना के एक मेजर और चार जवान भी मारे गए। पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने देश के लिए शहीद होने वाले पाकिस्तानी सैनिकों के अधिकारियों और जवानों की मौत पर संवेदना प्रकट की है।

इंकलाब (12 अक्टूबर) के अनुसार खैबर पख्तूनख्वा में आतंकियों के खिलाफ चलाए गए सैन्य अभियान में दो आतंकी मारे गए। यह मुकाबला डेरा इस्माइल खान के कुलाची क्षेत्र में हुआ। पाकिस्तानी गुप्तचर एजेंसी ने यह दावा

किया है कि मारे गए आतंकियों के हाथ वजीरिस्तान में हुए विभिन्न हमलों में पाए गए हैं। इनके कब्जे से पाकिस्तानी सेना से छीने गए काफी अस्त्र-शस्त्र भी बरामद हुए हैं।

बांग्लादेश में डेंगू महामारी जोरों पर

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (3 अक्टूबर) के अनुसार बांग्लादेश में डेंगू महामारी बड़ी तेजी से फैल रहा है। अब तक दो हजार से अधिक लोग इस महामारी का शिकार हो चुके हैं। बांग्लादेश के स्वास्थ्य महानिदेशक ने कहा है कि इस वर्ष दो लाख से अधिक डेंगू के रोगियों का पता चला है, जिनमें से दो हजार के लगभग लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में अधिकांश बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। पिछले साल बांग्लादेश में डेगू से तीन सौ के लगभग लोगों की मौत हुई थी। इस साल बांग्लादेश में भारी वर्षा हुई है, जिसके कारण डेंगू मच्छर भारी संख्या में पैदा हुए हैं। सरकार की ओर से डेंगू प्रभावित क्षेत्रों में मच्छरदानियां बांटी जा रही हैं और बांग्लादेश के सभी चिकित्सालयों को यह निर्देश दिया गया है कि वे डेंगू से प्रभावित रोगियों के इलाज के लिए विशेष चिकित्सा वार्ड बनाएं। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक भवनों में भी डेंगू से प्रभावित रोगियों को रखने की व्यवस्था की जा रही है।

इत्तेमाद (11 अक्टूबर) के अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि एशिया के अनेक देशों में डेंगू महामारी के रूप में फैल सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस संबंध में यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका के देशों को सतर्क किया है कि इस वर्ष डेंगू महामारी के रूप में अनेक क्षेत्रों में फैल सकता है। गौरतलब है कि पिछले साल डेंगू दक्षिणी यूरोपीय देशों और दक्षिण अमेरिका में महामारी के रूप में फैला था। इन क्षेत्रों में 50 हजार से अधिक लोग डेंगू की वजह से मरे थे और 45 करोड लोग इस महामारी का शिकार बने थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सभी देशों को यह निर्देश दिया है कि वे डेंगू का सामना करने के लिए इमरजेंसी की घोषणा करें और इसके निवारण के लिए आने वाली औषधियों का भंडारण भी कर लें, ताकि महामारी का सफलतापूर्वक सामना किया जा सके।

पश्चिम एशिया

क्या अरब–इजरायल संघर्ष तीसरे विश्व युद्ध का रूप लेगा?

अरब–इजरायल संघर्ष दिन प्रतिदिन तीव्र होता जा रहा है। विदेशी अखबारों में यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि यदि विश्व शक्तियां इस युद्ध को रोकने में सफल न हो सकीं तो यह तीसरे विश्व युद्ध का रूप ले सकता है। अखबार भी दो खेमों में बंट चुके हैं। एक खेमा इजरायल का समर्थन कर रहा है तो दूसरा खेमा फिलिस्तीनियों के समर्थन में मैदान में उतर गया है। जहां तक भारत के उर्दू अखबारों का संबंध है वे खुलेआम हमास और हिजबुल्लाह की आतंकी कार्रवाईयों का समर्थन कर रहे हैं।

इत्तेमाद (10 अक्टूबर) ने यह स्वीकार किया है कि इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने जो प्रयास किए थे, वह विफल रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इस मामले में काफी सक्रिय हैं और वे इजरायल और अरब देशों का दौरा करने की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले अमेरिका के विदेश मंत्री इजरायल, जॉर्डन और सऊदी अरब का दौरा कर चुके हैं।

इंकलाब (9 अक्टूबर) के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह घोषणा की है कि इस संकट की घड़ी में अमेरिका इजरायल के साथ खड़ा है और वह हर तरह की सहायता इजरायल को देगा।

रोजनामा सहारा (10 अक्टूबर) के अनुसार अमेरिका के तीन शक्तिशाली युद्धपोत इजरायल की जल सीमा की ओर बढ़ रहे हैं।

इत्तेमाद (10 अक्टूबर) के अनुसार अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने घोषणा की है कि उनका देश हमास के खिलाफ युद्ध लड़ने वाले इजरायलियों के समर्थन में पूर्वी भूमध्य सागर क्षेत्र में जंगी जलपोत और विमान भेज रहा है। यूएसएस फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर रवाना कर दिया गया है। इस बेडे में एक विमान वाहक जलपोत, एक गाइडेड मिसाइल क्रूजर और चार

गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शामिल हैं। अमेरिका के रक्षा मुख्यालय पेंटागन ने भी यह घोषणा की है कि अमेरिकी वायुसेना के एफ-35, एफ-15, एफ-16 और ए-10 के लड़ाकू विमान इजरायल भेजे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका इजरायल को अस्त्र-शस्त्र और अन्य साधन तेजी से उपलब्ध कराएगा। अमेरिका ने यह फैसला आतंकी संगठन हमास की तरफ से इजरायल पर हजारों रॉकेट फायर किए जाने के बाद किया है।

रोजनामा सहारा (8 अक्टूबर) के अनुसार हमास के हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री ने युद्ध की घोषणा कर दी है।

इत्तेमाद (9 अक्टूबर) के अनुसार रूस के राष्ट्रपति ने आजाद फिलिस्तीन की मांग का समर्थन किया है और इजरायल पर आरोप लगाया है कि वह विश्व को तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेल रहा है। रूस ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर इजरायल ने हमलों का सिलसिला नहीं रोका तो रूस भी इस संघर्ष में कूद सकता है।

इसी समाचारपत्र में प्रकाशित एक अन्य समाचार में हिजबुल्लाह के हमले को इजरायल के लिए घातक बताया गया है। समाचारपत्र ने कहा है कि अब इजरायल चारों तरफ से घिर गया है और इसके लिए इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू दोषी हैं।

इत्तेमाद (14 अक्टूबर) के अनुसार तुर्किये के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन इजरायल और फिलिस्तीनी नेताओं से बातचीत करके इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि इस युद्ध को रोका जाए।

मुंबई उर्दू न्यूज (10 अक्टूबर) के अनुसार ईरान ने कहा है कि अगर इजरायल ने गाजा पट्टी पर अपने हमले बंद न किए और नाकेबंदी को समाप्त नहीं किया तो ईरान मूकदर्शक बना नहीं रहेगा और वह फिलिस्तीनी जनता के हितों की रक्षा के लिए मैदान में कूद पड़ेगा।

इंकलाब (14 अक्टूबर) के अनुसार अमेरिका के विदेश मंत्री ने ईरान को चेतावनी दी है कि वह इस विवाद से दूर रहे, वरना उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

उर्दू टाइम्स (10 अक्टूबर) के अनुसार इजरायल ने यह आरोप लगाया है कि हमास ने इजरायल पर जो रॉकेट दागे हैं, उन्हें ईरान ने सप्लाई किए हैं।

हमारा समाज (11 अक्टूबर) के अनुसार ईरान ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा है कि इजरायल पर जो हमास का हमला हुआ है उसमें ईरान की कोई भूमिका नहीं है। इजरायल अपनी विफलता को छिपाने के लिए झूठे आरोप लगा रहा है। गाजा के फिलिस्तीनी समूहों ने धमकी दी है कि अब जंग रोकना नामुमकिन है। हम इजरायल का नामोनिशान मिटाकर ही दम लेंगे।

उर्दू टाइम्स (12 अक्टूबर) के अनुसार इजरायल ने फिलिस्तीनियों के घुसपैठ को रोकने के लिए जो आयरन डोम बना रखा था, वह रेत का साबित हुआ है और हमास के एक हजार से अधिक सशस्त्र आतंकी इजरायल में दाखिल हो गए हैं। अब इजरायल का खात्मा करीब है।

इसी समाचारपत्र में राम पुनियानी ने इस बात पर हैरानी प्रकट की है कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली गुप्तचर एजेंसी मोसाद इजरायल पर हमास के हमले के बारे में अपने नेताओं को कोई

भी जानकारी देने में विफल रही है। उन्होंने कहा है कि इसका कारण यह है कि इजरायल में विभिन्न गुटों के बीच जो गृहयुद्ध चल रहा है उसका लाभ हमास ने उठाया है।

इंकलाब (14 अक्टूबर) ने कहा है कि गाजा पर निरंतर हवाई जहाजों से बमबारी के बाद अब इजरायल ने गाजा पर जमीनी हमले की तैयारी शुरू कर दी है। गाजा के करीब और लेबनान की पूर्वी सीमा पर तीन लाख इजरायली सैनिकों को तैनात किया गया है और हजारों टैंक सीमा पर भेज दिए गए हैं।

इंकलाब (15 अक्टूबर) के अनुसार इजरायल ने गाजा की नाकेबंदी कर दी है, जिसके कारण वहां की जनता भूख और प्यास से तड़प तड़पकर दम तोड़ रही है। समाचारपत्र ने लिखा है कि गाजावासी अब कहां जाएं? क्योंकि मिस्र ने उन्हें अपनी सीमा में घुसने से रोक दिया है।

रोजनामा सहारा (14 अक्टूबर) का कहना है कि इजरायल गाजावासियों को वहां से बोरिया बिस्तर बांधकर भागने की धमकी दे रहा है। जबकि हमास ने कहा है कि गाजा के रहने वाले गाजा में ही डटे रहें और वे अपने घरों को छोड़कर कहीं न जाएं। उनकी जीत अब दूर नहीं है। ईरान ने यह धमकी दी है कि अगर इजरायल ने हमले बंद नहीं किए तो ईरान एक नया मोर्चा खोल सकता है।

रोजनामा सहारा (10 अक्टूबर) का कहना है कि गाजा की सीमा पर एक लाख इजरायली फौजी तैनात कर दिए गए हैं और इजरायल अब गाजा पर जमीनी हमला करने के लिए तैयार है।

रोजनामा सहारा (9 अक्टूबर) के अनुसार लेबनान से भी हिजबुल्लाह ने इजरायल पर हमले शुरू कर दिए हैं। इजरायल ने अपने बंधकों को छुड़ाने के लिए मिस्र से सहायता मांगी है।

उर्दू के लगभग सभी अखबारों ने अपने संपादकीय में इजरायल की निंदा की है और हमास और हिजबुल्लाह का समर्थन करते हुए कहा है कि अब यहूदियों का खात्मा दूर नहीं है।

हमारा समाज (13 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि मीडिया हमास को खलनायक बनाने की साजिश कर रहा है और उस पर बच्चों और महिलाओं की हत्या करने का बेबुनियाद आरोप लगा रहा है।

इत्तेमाद (13 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में इजरायल की निंदा करते हुए कहा है कि मोदी सरकार अपनी मुस्लिम विरोधी नीति के कारण फिलिस्तीनियों का विरोध और इजरायल का खुलकर समर्थन कर रही है। समाचारपत्र ने दावा किया है कि मोदी सरकार के इजरायल के साथ घनिष्ठ संबंध हैं। 1971 और 1999 के भारत-पाक युद्ध के दौरान इजरायल ने भारत को गोला बारूद और गुप्त सूचनाएं प्रदान की थी। 2017 के बाद से इजरायल भारत को सबसे ज्यादा अस्त्र-शस्त्र की आपूर्ति कर रहा है। मोदी सरकार इस मामले पर मुस्लिम विरोधी नीति अपना रही है ताकि वह

आने वाले चुनावों में बहुसंख्यक हिंदुओं के वोट प्राप्त कर सके।

इत्तेमाद (12 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि विश्व को इजरायल को जंग के जुनून से रोकना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि यह युद्ध विश्व युद्ध का रूप धारन कर ले।

अवधनामा (13 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि इजरायल ने गाजा की जो नाकेबंदी की है, वह अमानवीय है। समाचारपत्र ने यह भी आरोप लगाया है कि युद्ध के नियमों का खुला उल्लंघन करते हुए इजरायल गाजा में फास्फोरस बमों का इस्तेमाल कर रहा है।

अवधनामा (12 अक्टूबर) ने कहा है कि हमास और हिजबुल्लाह अब मस्जिद अल-अक्सा को इजरायल के चंगुल से मुक्त करके ही दम लेंगे।

उर्दू टाइम्स (12 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि अरब और फिलिस्तीन के युद्ध में हर न्यायप्रिय व्यक्ति फिलिस्तीन के पक्ष में है। अब मुस्लिम देशों के साथ-साथ गैर-मुस्लिम देशों ने भी फिलिस्तीन का खुलकर समर्थन किया है, जिनमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का नाम उल्लेखनीय है। जबकि कोलंबिया के राष्ट्रपति ने इजरायल की सेना की तुलना हिटलर की नाजी सेना से की है। स्पेन ने भी फिलिस्तीन का समर्थन किया है। समाचारपत्र ने अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा की जनता को इस बात की बधाई दी है कि वे फिलिस्तीनियों और हमास के समर्थन में सड़कों पर उतर आए हैं और वे इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं।

सियासत (11 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में इस बात की निंदा की है कि दुनिया के अधिकांश देशों ने इजरायल के आम नागरिकों पर हमले की तो निंदा की है। मगर उन्हें फिलिस्तीन के निहत्थे और बेबस आवाम नजर नहीं आती। ये लोग अपनी राजनीतिक मजबूरियों के कारण फिलिस्तीनी जनता के मामले में अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और सिर्फ इजरायल के चश्मे से हर मामले को देखते हैं।

रोजनामा सहारा (13 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि अब अरब देश भी एकजुट होकर फिलिस्तीनियों का समर्थन नहीं कर रहे हैं। उनका सारा ध्यान अमेरिका से दोस्ती स्थापित करने पर लगा हुआ है। इजरायल से अब्राहम समझौता कराकर अमेरिका ने मुस्लिम देशों को बता दिया है कि उनके लिए आजाद फिलिस्तीन या मस्जिद अल-अक्सा से ज्यादा उनके अपने निजी हित महत्त्वपूर्ण हैं। यही कारण है कि हमास के हमले के बाद मुस्लिम देशों के स्वर बदले बदले नजर आ रहे हैं। हर एक की अपनी डफली और अपना राग है। गाजा पर इजरायल की बमबारी के खिलाफ वे सिर्फ जबानी जमा-खर्च कर रहे हैं। वे हमास या फिलिस्तीनियों की सहायता के लिए कोई ठोस कदम उठाने के लिए तैयार नहीं हैं।

समाचारपत्र ने कहा है कि सऊदी अरब अमेरिका के दबाव पर गुप्त रूप से इजरायल से दोस्ती करने के लिए प्रयत्नशील है। जहां तक ईरान का संबंध है, वह भी अभी सिर्फ धमकियां देने में ही लगा हुआ है। जैसे ही इजरायल ने यह आरोप लगाया कि हमास के हमले के पीछे ईरान का हाथ है तो तुरंत ईरान ने अपने सुर बदल लिए। हालांकि, ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने घोषणा की है कि ईरान भी उसी तरह से फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा है जैसा अमेरिका और यूरोपीय देश इजरायल के साथ खड़े हैं। तुर्किये आर्थिक संकट में फंसा हुआ है। जब उसने फिलिस्तीन की तरफ ज्यादा झुकाव दिखाया तो उसकी करेंसी 'लीरा' की हालत पतली होने लगी। अब तुर्किये इजरायल के खिलाफ कोई कदम उठाने की बजाय इस युद्ध में मध्यस्थता करने में ज्यादा रुचि ले रहा है। इजरायल के नए दोस्तों में संयुक्त अरब अमीरात शामिल हो चुका है और उसने इजरायल पर हमास के हमले की निंदा की

है। जबकि बाकी मुस्लिम देश इस मामले में बंटे हुए हैं।

अरब-इजरायल विवाद

19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में पूर्वी यूरोपीय देशों के यहूदियों ने फिलिस्तीन में आना प्रारंभ कर दिया था। 1882 की जनगणना के अनुसार इस क्षेत्र में अरबों की आबादी साढ़े चार लाख थी। जबकि यहूदी जनसंख्या 25 हजार थी। 1920 से लेकर 1933 तक अरब यहूदियों के फिलिस्तीन में आने का विरोध करते रहे। फिलिस्तीनियों की मांग थी कि अंग्रेज फिलिस्तीन में यहूदियों के बसने पर रोक लगाएं। साल 1929 में टेंपल माउंट में पूजा के अधिकार को लेकर अरबों और यहूदियों में संघर्ष हुआ। यहूदी शोक दीवार पर प्रार्थना करना चाहते थे। उनका यह दावा था कि यह दीवार उनके उपासना स्थल का अवशेष है, जिसे रोमनों ने पहली ईस्वी शताब्दी में नष्ट कर दिया था। यहूदियों का यह पवित्र स्थल मस्जिद अल-अक्सा का एक भाग है। अरबों का आरोप है कि यहूदी मस्जिद अल-अक्सा को तबाह करके वहां पर अपना उपासना स्थल स्थापित करना चाहते हैं।

हिटलर ने यहूदियों के नरसंहार का जो अभियान चलाया था, उसके कारण 1936 तक फिलिस्तीन में तीन लाख 84 हजार यहूदी आ चुके थे। इस संघर्ष में और भी बढ़ोतरी हुई। 1937 में ब्रिटिश रॉयल कमीशन ने लॉर्ड पील के नेतृत्व में अपनी रिपोर्ट में यह सुझाव दिया कि फिलिस्तीन का दो राष्ट्रों में विभाजन कर दिया जाए। मगर अरबों ने इसे मानने से इंकार कर दिया। इसी दौरान दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया और पूर्वी यूरोप के देशों से यहूदियों के फिलिस्तीन में आने की गति तेज हो गई। इसके कारण यहां पर गृहयुद्ध शुरू हो गया। ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र से इस विवाद के बारे में हस्तक्षेप करने की मांग की, जिसने यह सुझाव दिया कि फिलिस्तीन का विभाजन किया जाए और यरुशलम का क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय नियंत्रण में रहे। यहूदियों ने इसे स्वीकार कर लिया। मगर अरब इस विभाजन के लिए तैयार नहीं थे।

ब्रिटेन ने इस क्षेत्र को खाली कर दिया और यहूदियों ने 15 मई 1948 को इजरायल की स्थापना की घोषणा कर दी। इस पर 1949 में पहला अरब-इजरायल युद्ध छिड़ गया, जिसमें मिस्र, लेबनान, जॉर्डन और सीरिया ने भाग लिया। इस युद्ध के बाद जो समझौता हुआ, उसमें अरब देश दो हजार वर्ग मील का क्षेत्र यहूदियों को देने के लिए तैयार हो गए और इसके कारण सात लाख फिलिस्तीनी अपने घरों से बेघर हो गए। क्योंकि उनके क्षेत्र पर इजरायल ने कब्जा कर लिया था। इजरायल की स्थापना के कारण अरब जगत में शासकों के प्रति विरोध की ज्वाला भड़क उठी। 1955 में मिस्र के सम्राट का तख्ता जमाल अब्दुल नासेर ने पलट दिया। इसके बाद अरब जगत में अस्त्र-शस्त्र इकट्ठा करने का दौर शुरु हुआ। मिस्र ने रूस से भारी मात्रा में अस्त्र-शस्त्र रूस और पूर्वी यूरोप के देशों से खरीदे। जबकि इजरायल ने वायुयान और अस्त्र-शस्त्र फ्रांस से भारी मात्रा में खरीदे। नासिर का तख्ता पलटने के लिए इजरायल ने ब्रिटेन और फ्रांस के साथ गुप्त समझौता किया। मध्य पूर्व में युद्ध को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विभिन्न देशों के सहयोग से यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी फोर्स नामक एक संगठन को स्थापित किया।

1967 में जॉर्डन नदी के पानी को लेकर अरब देशों और इजरायल के बीच जोरदार झड़पें हुईं। इजरायल के नेताओं ने 1967 में मिस्र के खिलाफ हमला बोल दिया। बाद में इस युद्ध में जॉर्डन भी शामिल हो गया। छह दिनों के युद्ध में इजरायल अरब देशों पर भारी पड़ा। इजरायल ने सिनाई प्रायद्वीप और गाजा मिस्र से, गोलेन हाइट्स सीरिया से और पूर्वी यरुशलम व वेस्ट बैंक जॉर्डन से छीन लिए। तीन लाख से अधिक शरणार्थियों को वेस्ट बैंक और गोलेन हाइट्स से भागकर जॉर्डन और सीरिया में शरण लेनी पड़ी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका और रूस पर दबाव डाला। इजरायल ने इस बात पर जोर दिया कि जब तक अरब देश उससे सीधी बातचीत नहीं करते और शांति समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करते तब तक वह किसी भी अधिकृत क्षेत्र को खाली नहीं करेगा।

इस युद्ध के बाद फिलिस्तीनियों के विभिन्न लड़ाकू गुट 1964 में स्थापित फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन (पीएलओ) में शामिल हो गए। यह संगठन इजरायली क्षेत्रों पर हमला करता रहा। 1973 में मिस्र और सीरिया ने इजरायल द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्रों को वापस लेने के लिए अचानक हमला कर दिया। संयुक्त राष्ट्र के दबाव पर इजरायल ने सीनाई का क्षेत्र मिस्र के हवाले कर दिया और अल-कुनीत्रा सीरिया के हवाले कर दिया गया। नवंबर 1977 में मिस्र के राष्ट्रपति अनवर अल-सादात ने यरुशलम का दौरा किया, जिससे अरब-इजरायल के नए रिश्तों की शुरुआत हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर के प्रयास से 1979 में कैंप डेविड में इजरायल और मिस्र के नेताओं के बीच बातचीत हुई और दोनों के बीच एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए।

1982 में इजरायल ने आरोप लगाया कि लेबनान पीएलओ का समर्थन कर रहा है। इसके बाद उसने लेबनान पर हमला बोल दिया। इजरायल ने लेबनान के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। 1980-1990 के दौरान इजरायल ने गाजा और वेस्ट बैंक पर अपने कब्जे को बरकरार रखा। इससे वहां पर रहने वाले फिलिस्तीनियों ने इजरायल के खिलाफ विद्रोह कर दिया और वहां पर गृहयुद्ध छिड़ गया। इसके बाद पीएलओ ने इजरायल पर हमले शुरू कर दिए। 1988 में संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार इजरायल को मान्यता प्रदान की। उसने इजरायल और स्वतंत्र फिलिस्तीन को मान्यता दी। इसके साथ ही फिलिस्तीन स्टेट का शासन पीएलओ के हाथों में सौंप दिया।

अल-अक्सा मस्जिद

अल-अक्सा मस्जिद शताब्दियों से यहूदियों, मुसलमानों एवं ईसाइयों के बीच विवाद की जड़ बनी हुई है। इस पवित्र स्थल के बारे में तीनों धर्मों द्वारा अलग-अलग दावे किए जाते रहे हैं। यहूदियों का दावा है कि यह मस्जिद यहूदी उपासना स्थल सोलोमन टेंपल के पुरावशेषों पर बनी हुई है, जिसे रोमनों ने पहली ईस्वी शताब्दी में ध्वस्त कर दिया था। उनका यह भी दावा है कि सोलोमन टेंपल उनके प्राचीन उपासना स्थल 'डोम ऑफ द रॉक' के अवशेषों पर बनाया गया था, जिसे आक्रांताओं ने कई बार ध्वस्त किया और यहूदी उसका पुनर्निर्माण कराते रहे। बाद में इस पर ईसाइयों के एक चर्च का निर्माण किया गया। 1187 में अरब आक्रांता सलाउद्दीन अयूबी ने यरुशलम पर विजय प्राप्त की और उसने चर्च को गिराकर वहां पर अल-अक्सा मस्जिद का निर्माण कराया। मगर

इसका निर्माण कार्य बाद के अन्य अरब शासक भी करते रहे। खास बात यह है कि दसवीं शताब्दी से पहले जिन मस्जिदों का निर्माण किया जाता था, उनका मुख्य द्वार यरुशलम की ओर होता था। बाद में जो मस्जिदें बनाई गई वह मक्का की ओर मुंह करके बनाई गई।

अरबों का यह भी दावा है कि मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर ने इसी स्थान के समीप एक मस्जिद का निर्माण किया था। जिसमें उमय्यद खलीफा मुआविया के शासनकाल में कुछ विस्तार किया गया, जिसे अंतिम रूप खलीफा अल-वलीद ने दिया था। मुसलमानों का यह भी मानना है कि यह मस्जिद भूकंप के कारण 746 में तबाह हो गई थी और इसका पुनर्निर्माण अब्बासी खलीफा अल-मंसूर ने किया था, जोकि 1033 में आए भूकंप के कारण फिर से तबाह हो गया, जिसका पुनर्निर्माण सलाउद्दीन अयूबी ने यरुशलम को विजय करने के बाद किया। मुसलमानों की दृष्टि में अल-अक्सा मस्जिद तीसरा सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। पहला स्थान मक्का में स्थित काबा और दूसरा स्थान मदीना में हजरत मोहम्मद द्वारा बनाई गई मस्जिद-ए-नबवी को प्राप्त है।

फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन

फिलिस्तीन लिबरेशन आर्गेनाइजेशन (पीएलओ) का गठन 1964 में किया गया था। बाद में इसके नेता रूस समर्थक यासिर अराफात बने। अराफात के स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से भी घनिष्ठ संबंध थे। प्रारंभ में आसिर अराफात पीएलओ के सैनिक विंग अल-फतह के नेता थे। मगर बाद में वे पीएलओ के अध्यक्ष बन गए। 1970 में पीएलओ का सशस्त्र संघर्ष जॉर्डन के शाह हुसैन से शुरू हुआ। 1971 में जॉर्डन की सेना ने पीएलओ को जबर्दस्ती जॉर्डन से बाहर निकाल दिया। 1974 में अरब देशों ने पीएलओ को फिलिस्तीनी अरबों के संगठन के रूप में मान्यता प्रदान की और उसे अरब लीग में एक सदस्य के रूप में शामिल किया गया। मगर खास बात यह है कि 1979 में कैंप डेविड में मिस्र और इजरायल के नेताओं के बीच जो वार्ता हुई थी, उसमें पीएलओ को शामिल नहीं किया गया था।

इजरायल ने सिनाई प्रायद्वीप का क्षेत्र तो मिस्र को वापस कर दिया था। मगर उसने वेस्ट बैंक और गाजा का शासक पीएलओ को मानने से इंकार कर दिया। मिस्र के सख्त रूख को देखते हुए आसिर अराफात ने पीएलओ का मुख्यालय बेरूत से ट्यूनीशिया स्थानांतरित कर लिया। अरब देशों में बढ़ते हुए विरोध को देखते हुए यासिर अराफात ने इजरायल के प्रति अपनी नीति को उदार बनाया। नवंबर 1988 में पीएलओ ने यह दावा किया कि वह फिलिस्तीन का शासक है। 1989 में पीएलओ को निर्वासित सरकार के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई। 1990-91 की खाड़ी युद्ध में अराफात ने इराक का समर्थन किया, जिसके कारण खाड़ी के देश उनसे नाराज हो गए।

1993 में पीएलओ ने अराफात के नेतृत्व में इजरायल के साथ गुप्त समझौता किया और इन दोनों के बीच ओस्लो समझौता हुआ, जिस पर 1993 में अराफात और इजरायली नेताओं ने हस्ताक्षर किए। इस समझौते में यह व्यवस्था की गई थी कि वेस्ट बैंक और गाज को धीरे-धीरे नवगठित फिलिस्तीन अथॉरिटी के हवाले किया

जाएगा। इस अथॉरिटी के पहले राष्ट्रपति आसिर अराफात बने। मगर बाद में यह प्रयास विफल हो गया। 2004 में यासिर अराफात की मृत्यु के बाद महमूद अब्बास, जो पीएलओ के सैनिक विंग अल-फतह के वरिष्ठ सेनापति थे, फिलिस्तीन अथॉरिटी के राष्ट्रपति बने। 2007 में पीएलओ और हमास के बीच सशस्त्र संघर्ष गाजा पट्टी के कब्जे को लेकर हुआ और बाजी हमास के हाथ में लगी। इसके बाद महमूद अब्बास ने हमास के नेतृत्व वाली विधायिका को भंग कर दिया और उसके स्थान पर एक आपातकालीन कैबिनेट का गठन किया। इस पर फिलिस्तीन अथॉरिटी और हमास के बीच संघर्ष चलता रहा। संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन अथॉरिटी को गैर-सदस्य पर्यवेक्षक का दर्जा दे दिया। इजरायल तब से वेस्ट बैंक और गाजा क्षेत्र में यहूदी बस्तियां बसाकर वहां की आबादी के अनुपात को बदलने का प्रयास करता आ रहा है।

हमास

जहां तक हमास का संबंध है, उसका अरबी नाम हरकत अल-मुकावामा अल-इस्लामिया है। इसकी स्थापना 1987 में फिलिस्तीन के एक इमाम और मुस्लिम ब्रदरहुड के सक्रिय सदस्य शेख अहमद यासीन ने की थी। हमास को मुस्लिम ब्रदरहुड का राजनीतिक विंग कहा जाता है। प्रारंभ में हमास का लक्ष्य फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के प्रभाव को समाप्त करना था। इजरायल का यह प्रयास था कि फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद को प्रोत्साहन देकर हमास के मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ संबंधों को कमजोर किया जाए। 1988 में हमास ने अपना एकल सूत्रीय घोषणापत्र जारी किया, जिसका लक्ष्य इजरायल को हर कीमत पर नेस्तनाबूद करना था। 1993 में हमास ने पहला आत्मघाती हमला यासिर अराफात और इजरायल के बीच हुए ओस्लो समझौते में पलीता लगाने के लिए किया। उसने पीएलओ और इजरायल के बढ़ते हुए संबंधों को इस्लाम और अरब के लिए घातक बताया। 1997 में अमेरिका ने हमास को विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया। इन दिनों गाजा पट्टी हमास के नियंत्रण में है और इस्माइल हानिया इस आतंकी संगठन का प्रमुख है। इसका मुख्यालय कतर की राजधानी दोहा में है। क्योंकि मिस्र ने उसकी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा रखा है और उसे गााजा में कदम रखने की अनुमति नहीं है। मिस्र के वर्तमान शासक अब्देल फतह अल-सिसी मुस्लिम ब्रदरहुड के सख्त विरोधी हैं। गाजा में हमास का प्रमुख आह्या सिनवार है और वह कई सालों तक इजरायली जेल में बंद रहा है। उस पर कुछ इजरायली सैनिकों का अपहरण करके उनकी हत्या करने का आरोप था। 2011 में हमास द्वारा बंधक बनाए गए इजरायली सैनिकों की रिहाई के बदले में इजरायल ने सिनवार को जेल से मुक्त किया था। सालेह अल-अरौरी हमास के

लेबनान शाखा का प्रमुख है और उसके नियंत्रण में वेस्ट बैंक का इलाका भी है। इसके अन्य नेताओं में सलामेह कटावी और खालिद मशाल शामिल हैं।

हिजबुल्लाह

हिजबुल्लाह लेबनान में सक्रिय शिया आतंकी संगठन है। इसके तार सीधे ईरान से जुड़े हुए हैं। हिजबुल्लाह को भी अमेरिका और कई अन्य यूरोपीय देशों ने आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। हाल ही में ईरान और सीरिया के सहयोग से हिजबुल्लाह सैन्य रूप से काफी सक्रिय हो गया है और वह इजरायल के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द माना जाता है। लेबनान में चले 15 साल के गृहयुद्ध के दौरान हिजबुल्लाह काफी ताकतवर हुआ है। लेबनान की सरकार को सत्ता में लाने और बेदखल करने में हिजबुल्लाह की भूमिका 1992 से ही रही है। 2005 में लेबनान में हुए चुनाव में हिजबुल्लाह के कई सदस्य संसद के लिए चुने गए थे और लेबनान सरकार में हिजबुल्लाह के मंत्री भी शामिल हैं। 2022 में लेबनान में जो चुनाव हुए उसमें लेबनान के 128 सदस्यीय संसद में हिजबुल्लाह को 13 सीटें प्राप्त हुई थीं। मगर हिजबुल्लाह की समर्थक पार्टी चुनाव में हार गई थी। सीरिया में चल रहे गृहयुद्ध में हिजबुल्लाह की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।

तुर्किये की संसद पर आतंकी हमला

इंकलाब (2 अक्टूबर) के अनुसार तुर्किये की राजधानी अंकारा स्थित संसद पर आतंकियों ने हमला किया। इस हमले में दो पुलिसकर्मियों के जख्मी होने का दावा किया गया है। जबकि सेना की जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी आत्मघाती धमाके में मारा गया। वहीं दूसरे आतंकी को सेना ने गोली मारकर हत्या कर दी। तुर्किये के गृह मंत्रालय के अनुसार यह आतंकी हमला था। इससे पहले 2011 में भी संसद पर हमला किया गया था। दो आतंकी सैनिक गाड़ी में बैठकर संसद के सभी सुरक्षा प्रबंधों को तोड़ते हुए संसद परिसर में घुस आए, जिन्हें सेना ने मार गिराया। तुर्किये के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने दावा किया है कि इन आतंकियों को सीरिया में प्रशिक्षित किया गया था और इस हमले के पीछे सीरिया की सरकार का हाथ है।

रोजनामा सहारा (3 अक्टूबर) के अनुसार इस हमले के बाद तुर्किये की वायु सेना ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के 20 ठिकानों पर हमले किए। तुर्किये की सेना ने उत्तरी इराक में भारी बमबारी की। तुर्किये की सरकारी टेलीविजन पर तुर्किये के विदेश मंत्री हैकन फिदान ने कहा है कि हमारी संसद पर हमला करने वालों को हम किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेंगे और हम उनके ठिकानों को हर कीमत पर तबाह करेंगे। तुर्किये की रक्षा मंत्रालय

ने दावा किया है कि तुर्किये के गुप्तचर एजेंटों ने उस आतंकी को सीरिया में घुसकर मौत के घाट उतार दिया है, जिसने पिछले साल इस्तांबुल में हुए बम धमाकों की योजना बनाई थी। इस धमाके में 12 लोग मारे गए थे।

इंकलाब (5 अक्टूबर) के अनुसार तुर्किये सरकार ने यह ऐलान किया है कि जिन लोगों ने तुर्किये की संसद पर हमला किया था, उन्हें सीरिया के गुप्त शिविरों में प्रशिक्षण दिया गया था। इस हमले की जांच करने वाली तुर्किये की गुप्तचर एजेंसियों को इस बात के ठोस प्रमाण मिले हैं कि दोनों आतंकी सीरिया से आए थे और उन्हें वहीं गुप्त शिविरों में प्रशिक्षित किया गया था। इन गुप्त शिविरों का संचालन कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के आतंकियों द्वारा किया जा रहा था। प्रवक्ता ने कहा कि इन शिविरों के संचालन में सीरिया सरकार की भी परोक्ष रूप से भूमिका थी।

रोजनामा सहारा (7 अक्टूबर) के अनुसार तुर्किये की सेना ने उत्तरी सीरिया में कुर्दिस पीपुल्स डिफेंस यूनिट के ठिकानों पर गोलीबारी करके तीन दर्जन से अधिक आतंकियों को मारने का दावा किया है। तुर्किये की रक्षा मंत्रालय के अनुसार तुर्किये की संसद पर हुए आतंकी हमले के जवाब में यह कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त तुर्किये की वायुसेना ने दाबिक क्षेत्र में भी हवाई हमले किए, जिसमें 100 से अधिक लोगों के मारे जाने का दावा किया गया है। तुर्किये की सरकार का यह दावा है कि इस हमले के परिणामस्वरूप आतंकियों के 100 से अधिक स्थानों को तबाह किया गया है।

मुंबई उर्दू न्यूज (6 अक्टूबर) के अनुसार तुर्किये की संसद पर आतंकी हमले के बाद तुर्किये की गुप्तचर विभाग ने पूरे देश में आतंकियों की गिरफ्तारियों का सिलसिला तेज कर दिया है। अब तक 167 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनका संबंध आतंकियों से बताया जा रहा है। तुर्किये के गृह मंत्री अली येरलिकाया ने संवाददाताओं को बताया कि गुप्तचर विभाग ने तुर्किये के 16 सूबों में छापेमारी करके जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनका संबंध प्रतिबंधित संगठन कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी से है। यह पार्टी पिछले दस सालों से कुर्दिस्तान में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रही है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन इस पार्टी को आतंकी संगठन घोषित कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये आतंकी 1984 से सक्रिय हैं और वे अब तक चार लाख लोगों को मार चुके हैं। तुर्किये के गृह मंत्री ने इराक और सीरिया को चेतावनी दी है कि वे आतंकी संगठनों से दूर रहें, वरना उन्हें भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।

सऊदी अरब में 21 वर्ष से कम उम्र के घरेलू कर्मचारी रखने पर प्रतिबंध

रोजनामा सहारा (8 अक्टूबर) के अनुसार सऊदी अरब में 21 वर्ष के कम उम्र के घरेलू कर्मचारी रखने पर कानूनी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस संबंध में सऊदी अरब के सरकारी गजट में जारी आदेश में कहा गया है कि जो लोग इस प्रतिबंध का उल्लंघन करेंगे उन पर 20 हजार रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। मालिकों और कर्मचारियों के बीच विवाद होने की सूरत में सऊदी अरब का समाज कल्याण विभाग शिकायतों की सुनवाई करेगा और दोनों पक्षों के बीच समझौता करवाने का प्रयास करेगा। किसी कर्मचारी को नौकरी पर रखने के बारे में किया जाने वाला समझौता 12 महीने की अवधि का होगा। इस अवधि के बाद इस समझौते का नवीनीकरण करना आवश्यक होगा।

नरगिस मोहम्मदी को नोबेल पुरस्कार दिए जाने की ईरान द्वारा आलोचना

रोजनामा सहारा (8 अक्टूबर) के अनुसार ईरान की विदेश मंत्रालय ने सरकार विरोधी प्रदर्शनों में भाग लेने और सरकारी नीतियों की आलोचना करने के कारण जेल में बंद मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को शांति का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की सख्त आलोचना की है और कहा है कि स्वीडन सरकार का यह कदम ईरान के आंतरिक मामले में अनुचित हस्तक्षेप है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने कहा कि नोबेल शांति पुरस्कार कमेटी ने यह पुरस्कार एक ऐसी महिला को दिया है, जोकि ईरानी कानून का बार-बार उल्लंघन करती रही हैं और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रही हैं। यह फैसला कुछ यूरोपीय देशों की ईरान विरोधी नीति के कारण लिया गया है। गौरतलब है कि नरगिस मोहम्मदी की गणना मानवाधिकारों के लिए लड़ने वाली विश्व की प्रमुख महिलाओं में होती है। वह ईरान सरकार द्वारा हजारों लोगों को फांसी देने का खुलकर विरोध करती रही हैं और इस बात की मांग करती रही हैं

कि ईरान में सजा-ए-मौत पर प्रतिबंध लगाया जाए। पिछले डेढ़ वर्ष से ईरान में हिजाब के खिलाफ महिलाओं द्वारा जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया जा रहा है उसका समर्थन भी नरगिस मोहम्मदी ने किया है। नरगिस इस समय तेहरान की बदनाम जेल एविन में कैद हैं। उन्हें अब तक 31 साल की कैद और 154 कोड़े मारने की सजा भी दी जा चुकी है। नरगिस दो बच्चों की मां हैं।

इंकलाब (7 अक्टूबर) के अनुसार नोबेल शांति पुरस्कार कमेटी की अधिकृत घोषणा के अनुसार इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार ईरान की जिस मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है उन्हें सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के आरोप में 13 बार गिरफ्तार किया जा चुका है। 51 वर्षीय नरगिस मोहम्मदी शांति का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली 19वीं महिला हैं। नोबल पुरस्कार प्राप्त करने वाले को एक मिलियन डॉलर का ईनाम भी दिया जाता है।यह पुरस्कार 10 दिसंबर को नरगिस मोहम्मदी के किसी वारिस को दिया जाएगा, क्योंकि इस समय नरगिस तेहरान की एक जेल में बंद हैं। नरगिस मोहम्मदी 2013 में शांति का पुरस्कार पाने वाली एक अन्य ईरानी महिला शिरीन एबादी द्वारा गठित एक संगठन डिफेंडर ऑफ ह्यूमन राइट्स सेंटर की उपाध्यक्ष भी हैं।

सीरिया में सैन्य अकादमी पर ड्रोन हमले में 100 से अधिक कैडेटों की मौत

इंकलाब (7 अक्टूबर) के अनुसार सीरिया के केंद्रीय सूबा होम्स में स्थित सीरियाई सैन्य अकादमी पर हुए एक ड्रोन हमले में कम-से-कम 100 से अधिक कैडेट और सैन्य अधिकारी मारे गए। जबकि 250 से अधिक लोग जख्मी हो गए। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार सीरिया के रक्षा मंत्री सैन्य अकादमी में आयोजित एक समारोह में भाग लेने के बाद जैसे ही बाहर निकले तीन ड्रोनों ने अकादमी पर हमला कर दिया। अभी तक इस आतंकी हमले की किसी भी संगठन ने जिम्मेवारी नहीं ली है। सीरिया की रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा है कि इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इस हमले के बाद सीरिया की वायुसेना ने सीरिया के विद्रोहियों के कब्जे वाले क्षेत्र पर अंधाधुंध बमबारी की। अभी तक यह मालूम नहीं चल सका है कि इस बमबारी में विद्रोहियों का कितना जान व माल का नुकसान हुआ है। संवाद समिति 'रॉयटर्स' की रिपोर्ट के अनुसार सैन्य अकादमी पर हुए ड्रोन हमले के बाद चारों ओर मृतकों की लाशें पड़ी हुई थीं और फर्श पर खून बिखरे हुए थे। घायल खून के तालाब में लेटे हुए आखिरी सांस ले रहे थे। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि इस धमाके के बाद काफी देर तक फायरिंग की आवाज भी सुनाई देती रही। मगर यह स्पष्ट नहीं है कि गोली चलाने वाले कौन थे? सीरिया की रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अभी तक सीरिया में जो आतंकी हमले हुए हैं यह उनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक और भीषण है।

गौरतलब है कि सीरिया में पिछले 12 सालों से गृहयुद्ध चल रहा है। जब बशर अल-असद के नेतृत्व में सेना ने शासन की बागडोर संभाली थी तो उनके खिलाफ देश में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी थी। इस विद्रोह को दबाने के लिए बशर अल-असद ने सैनिक शक्ति का अंधाधुंध प्रयोग किया था। अब तक इस गृहयुद्ध में पांच लाख से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और 50 लाख लोग बेघर हो गए हैं।

RNI No. DELHIN/2017/72722

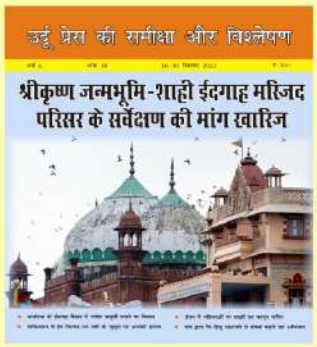

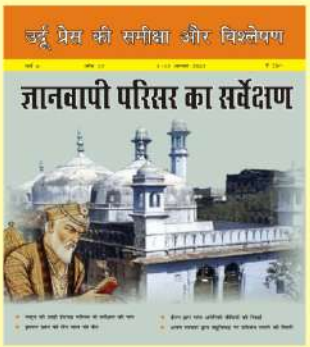

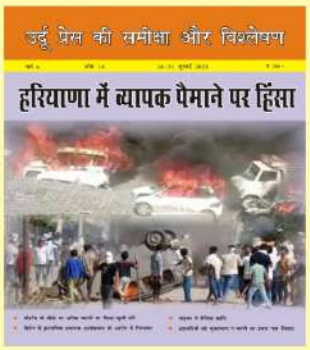

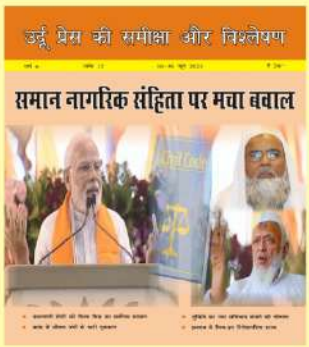

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in